1185
01/02/16

खण्ड-10 संख्या-12

एकादश

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भाग- 2

कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित

शुक्रवार, तिथि 10 जुलाई 1998 ई०

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष - माननीय सदस्य, खगेन्द्र बाबू आप जरा बैठ जायें।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा - उपाध्यक्ष महोदय, सरकार अपनी घोषणाओं के प्रति सचेत है और कार्रवाई कर रहीं है। माननीय सदस्य ने जो कहा उसको हम दिखवा लेते हैं। यहां घोषणा हुयी है और माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसको पूरा करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष - माननीय सदस्य, श्री खगेन्द्र जी आप बैठ जांय। मैं अंत में यही कहता हूँ कि जो माननीय सदस्य घटना स्थल पर गये थे और उनके पास जो अतिरिक्त सूचना है वे मंत्री से मिलकर बता दें। मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि उनकी सूचनाओं के आलोक में कार्रवाई हेतु नोटिस लेंगे।

अब वित्तीय कार्य होगा।

वित्तीय कार्य वर्ष १९९८-९९ के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद तथा मतदान

गृह विभाग (स्वीकृत)

उपाध्यक्ष - माननीय मंत्री।

श्री जगदानंद सिंह - महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

"गृह विभाग" के संबंध में ३१ मार्च, १९९९ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए १२,४६,८२,०८,००० (बारह अरब, छियालीस करोड़, बेरासी लाख, आठ हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल के सिफारिश पर किया गया है।

उपाध्यक्ष - इस पर जेनरल नेचर का जो कटौती प्रस्ताव है जिस पर सभी माननीय सदस्य विचार कर सकते हैं मैं, उसी को लेता हूं।

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह, श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री प्रेम कुमार एवं श्री वृषिण पटेल का १८४ से १८८ तक व्यापक है। अतः माननीय सदस्य, श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह अपना कटौती प्रस्ताव मूव करें।

कटौती प्रस्ताव

राज्य सरकार की गृहनीति पर विचार-विमर्श

(अस्वीकृत)

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय, राज्य सरकार की गृह नीति पर विचार विमर्श करने के लिये।

महोदय, माननीय मंत्रीजी का पुलिस बजट पर 94-95 में 5,40,89,775 रुपये खर्च हुआ, 95-96 में 5,90,65,139 96-97 में 6,65,97,550 97-98 में 8,15,25,153 खर्च किया और 98-99 में प्रस्तावित है 12,46,82,800 रुपयें।

महोदय, बजट में मंत्रीजी से कहना है कि कहीं भी एस०एस० मनी का उल्लेख नहीं किया गया है। एस०एस० मनी सेक्रेट फंड होता है और यहां पर सरकार से हमलोगों ने पूछा था कि असेस मनी जो सरकार देती है,

उसका सेट अप ठीक से नहीं मिलता है। क्या सरकार को जानकारी नहीं होनी चाहिये? महोदय, सरकान ने एस०एस० मनी में 96-97 में 38 लाख, 97-98 में 43 लाख खर्च किया है।

(व्यवधान)

कैसे सूचना मिलती है, यह हम और आप दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। कोई हिसाब किताब नहीं है। एस०एस० मनी का क्या काम है? जो जिला स्तर पर दारोगा, सी०आई०डी० यहां तक कि एस०पी० तक, वह पैसा कहां जाता है ? पिछले साल भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ एस०एस० मनी मैं, पहले जो राजकिशोर प्रसादजी थे, चले गये, रिटायर हो गये और उनकी जगह पर किसी को रख दिया गया, कौन हैं? उनके पुत्र को रख दिया गया। आखिर एस०एस० मनी के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, यह क्या हो रहा है? यह सेक्रेट फंड न तो धरातल पर जाता है, न इंस्पेक्टर-सब इंस्पेक्टर को मिलता है, मुखबिरों को देने के लिये, पता लगाने के लिये आखिर कहां जाता है, यह तो पता रखियेगा न? प्रभारी मंत्रीजी इसका जवाब भी दें।

उपाध्यक्ष - सेक्रेट मनी का जब जवाब दे देंगे तो सेक्रेट कहां रहेगा ?

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह - यह नहीं कहेंगे कि किस जिले में किस काम के लिये गयी, यह तो नहीं देंगे, लेकिन राज्य स्तर पर इस पर कितना खर्च है, जिलावार कितना दिया गया, यह तो देंगे।

महोदय, बिहार में पुलिस की क्या स्थिति है? बिहार में एक लाख पर 84 पुलिस है, दिल्ली में एक लाख पर 462 पुलिस है, गुजरात में एक लाख पर 147 पुलिस है।

महोदय, एक हजार जनसंख्या के लिये पुलिस कर्मचारियों की संख्या क्या है ? आंध्र प्रदेश में 10, गुजरात में 15, कर्नाटक में 11, मध्य प्रदेश में 14, महाराष्ट्र में 16, उड़ीसा में 11, पश्चिम बंगाल में 12 और बिहार में 9 जबकि राष्ट्रीय औसत है 137 ।

महोदय, प्रति सिविल पुलिसकर्मी के लिये मामलों की संख्या है :-

आंध्रप्रदेश में 1.7, गुजरात में 1.8, कर्नाटक में 2.0, उत्तर प्रदेश में 1.7 पश्चिम बंगाल में 1.5 और बिहार में 2.8।

महोदय, पुलिस बजट बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना पड़ेगा, किसी की भी सरकार रहेगी तो उसकी बढ़ोत्तुरी होगी, लेकिन उसका रिटर्न क्या हो रहा है ? स्थिति यह है-90 में जातीय हत्याएं 51, सियासी हत्याएं 27, 91 में जातीय 110, सियासी 31, 92 में जातीय 167, सियासी 24, 93 में जातीय 78 सियासी 50, 94 में जातीय 52 सियासी 65, 95 में जातीय 56 सियासी 32, 96 में जातीय 104 सियासी 68, 97 में जातीय 217 सियासी 46 एवं 98 में मई तक जातीय 93, सियासी 55 ।

उपाध्यक्ष महोदय, फिरौती के लिए अपहरण की घटनाएँ 1991 में 289 हुई, 1992 में 295, 1993 में 290, 1994 में 398, 1995 में 346, 1996 में 340 एवं 1997 में 42 घटनाएं हुई है। महोदय, उसी तरह से अपहरण की घटनाएं 1991 में 2170, 1992 में 2308, 1993 में 2387, 1994 में 2309, 1995 में 2182, 1996 में 2420 एवं 1997 में 2472 अपहरण की घटनाएँ हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह आँकड़ा गृह विभाग से प्राप्त आँकड़ा के अनुसार 90 से 97 के बीच 342 राजनैतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। उसी तरह से महोदय, 1990 से 97 तक सामुहिक नरसंहार, जातीय संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष में मौत के घाट उतारे गये लोगों की संख्या 17,500 तक पहुँच गयी है। उसीतरह से महोदय, भूमि विवाद में हर साल औसतन 70 से 200 लोग मारे गये है। एक मोटे आँकड़े के अनुसार 1990 में नरसंहारों की नौ घटनाओं में 51 लोग मारे गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 1991 में 15 नरसंहारों में 110 लोग मारे गये हैं, 1992 में 23 नरसंहारों में 75 लोग मारे गये हैं, 1993 में 12 नरसंहारों में 75 लोग मारे गये, 1994 में 9 नरसंहारों में 52 लोग मारे गये; 1995 में 11 नरसंहारों में 56 लोग मारे गये, 1996 में 15 नरसंहारों में 104 और 1997 में 26 नरसंहारों में 217 लोग मारे गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 1990 से 97 तक

राजनीतिक हत्याओं के सरकारी आँकड़े इस प्रकार हैं:- 1990 में 27, 1992 में 24, 1993 में 50 1994 में 65, 1995 में 32, 1996 में 68 और 1997 में 46 राजनीतिक हत्या हुई हैं उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सात वर्षों में अपराध के 8 लाख 66 हजार 619 मामले दर्ज हुए, जिसमें 33724 हत्यां, 7310 बलात्कार, 15621 अपहरण और नरसंहारों की लंबी कतार है।

उपाध्यक्ष महोदय, अपराध का 1998 में जनवरी से मई का फीगर मैं देता हूँ। महोदय, अपराध का 1998 के जनवरी माह में 10079, फरवरी में 9497, मार्च में 1175, अप्रैल में 10831, मई में 11823 यानि कुल मिलाकर 53405 अपराध की घटना हुई है। उसीतरह से महोदय, हत्या का जनवरी में 351, फरवरी में 353, मार्च में 454, अप्रैल में 493 एवं मई में 561 यानि कुल 2212 हत्याएँ 1998 में हुई हैं। उसी तरह से महोदय डकैती की कुल घटनाएँ जनवरी में 215, फरवरी में 137, मार्च में 250, अप्रैल में 199 एवं मई में 194 यानि कुल 995 डकैती की घटनाएँ हुई हैं। उसीतरह से दंगा का 1998 का जनवरी माह में 732 घटनाएँ हुई है, फरवरी में 898, मार्च में 1147, अप्रैल में 995 एवं मई में 1040 दंगा की घटनाएं हुई है। उसीतरह से महोदय, बैंक रौबरी की 1998 में निम्न घटनाएँ हुई है। जनवरी 98 में बैंक रौबरी 2 फरवरी, में 0, मार्च में 4, अप्रैल में 2, मई में 3 बैंक रौबरी की घटनाएँ इस प्रदेश में घटी है। उसीतरह से महोदय, बैंक डकैती 98 के जनवरी माह में 1, फरवरी माह में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 1 एवं मई में 3 घटनाएँ हुई है, जिसमें कोतवाली के सामने बैंक डकैती भी शामिल है।

श्री विनोद कुमार यादवेन्दु - उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ। माननीय सदस्य ने एक कमपरेटिव स्टेटमेंट दिया है कि इतना हजार पर इतना बल है। हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य से जानना चाहते हैं कि उत्तरप्रदेश में और खासकर जहाँ के देश में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी आते हैं, वहाँ एक वर्ष भी नहीं हुआ और 250 हत्याएँ हुई है।

(व्यवधान)

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह – माननीय सदस्य यादवेन्दु जी, माननीय मंत्री जब जवाब देंगे, तब वे बतायेंगे कि क्या स्थिति है, अभी आप धैर्य रखे। अगर मैं कोई गलत कह रहा हूँ तो मंत्री जी जवाब देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, राजधानी में कुछ दिनों के बीच 38 अपहरण के मामले दर्ज हुए हैं। व्यापायियों के अपहरण का एक नया उद्योग खुल गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कहा गया है कि विशेष कर भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी आदि शहरों से व्यापारियों का पलायन हो रहा है। वनांचल का इलाका आतंक, दमन से परेशान है। राज्य का सीमावर्ती इलाका पूरी तरह असुरक्षित है। नेपाल और बंगलादेश की सीमावर्ती इलाका अन्तरराजीय, अन्तर्राष्ट्रीय अपराध केकमियों का अड्डा बना हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, बिहार माड़वाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष के अनुसार पिछले 8 साल में 10,000 व्यवसाई कारवार समेट रहे हैं और इसके लिए अपहरण और असुरक्षा का माहौल जिम्मेवार है। बिहार चेम्बर ऑफ कॉमर्स ऐंड इन्डस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष श्री पी०के०अग्रवाल ने कहा है कि पिछले दो दशक में क़ानून और व्यवस्था की ख़राब हालत के चलते 5,000 छोटे, मझोले उद्योग बंद हो गये हैं। बिहार में हर जगह रंगदारी टैक्स माँगा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रभात खबर में यह समाचार निकला है कि हर दिन सिपाही बहाल करते रहे सक्सेना। महोदय, इसमें निकला है कि तत्कालीन पुलिस महानिर्देशक श्री एस०के०सक्सेना ने लगभग 500 सिपाहियों की नियुक्ति की, अपनी सेवानिवृति के अंतिम दिन श्री सक्सेना ने आठ सिपाहियों को भरती किया, महोदय, पिछले एक साल में उन्होंने तकरीबन तीन सौ नियुक्तियाँ की और उसके पहले के वर्ष में दो सौ नियुक्तियाँ की है। यह महोदय, मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यह प्रभात खबर में दिनांक 30 मई को निकला है, वह मैं कह रहा हूँ।

महोदय, अगर इस तरह का कार्य प्रदेश का एक करे। गृह विभाग प्रदेश का मुख्य अंग होता है और डी०जी०पी० इस तरह की बात करते हैं यह बड़े

शर्म की बात है। यह इन पर एक प्रश्न-चिह्न खड़ा होता है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो इस पर भी जबाव दें।

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 8 जुलाई के टाईम्स ऑफ इन्डिया में निकला है कि पुलिस विभाग में डेहरी-ऑन-सोन थाना में पदस्थापित एस०आई० श्री जे०पी० राधा का स्थानान्तरण डी०जी०पी० द्वारा इसलिएफर दिया गया कि एक सातिर डकैत को गिरफ्तार किया गया था। उस को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। मैं नहीं कहता हूं कि किस राजनीतिक दल का सरंक्षण उस को प्राप्त था लेकिन प्राप्त था और उस पर वहां के आरक्षी अधीक्षक श्री अम्बेदकर ने अपना विरोध जताते हुए मुख्यालय को लिखा है कि इस तरह की कार्रवाई से पुलिस का मनोबल गिरेगा। इसलिए श्री राणा को पुनः पूर्व स्थान पर पदस्थापित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां कुछ मुख्य घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। तिसखोरा कांड में 15 व्यक्ति मारे गये, देव सहियार (भोजपुर) कांड में 15 व्यक्ति मारे गये, मारा (गया) में 32 व्यक्ति मारे गये, बथारी टोला कांड में 21 व्यक्ति मारे गये, चतरा में 12 आदमी मारे गये, लक्ष्मणपुर बाथे कांड में 61 व्यक्ति मारे गये, पालीगंज में 11 व्यक्ति मारे गये और भोजपुर में 8 व्यक्ति मारे गये। और महोदय, अभी कुछ दिन पूर्व बगोदर में सात व्यक्ति मारे गये हैं। माननीय सदस्य श्रीमहेन्द्र प्रसाद सिंह जी ने भी इसका जिक्र किया था और इस पर काफी चर्चा भी हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करता हूं कि वह इसका भी जबाव देंगे।

पुलिस कमीशन 1961 का जो रिपोर्ट है उसकी कुछ पंक्तियां यहां उद्धत करना चाहता हूं-''अनुसंधान का स्तर बहुत घटिया है। अनुसंधान का काम जिस रीति से होता है, उस में सुधार की आवश्यकता है। पुलिस कर्मचारी ऑम तौर से अकुशल, प्रायः दीर्घसूत्री (विलंबकारी) उदासीन और बेईमान भी होते हैं। अनुसंधान अफसरों को असलिप्त को पता लगाने की

चिन्ता नहीं रहती, वह दोष सिद्ध कराने का ही खास मतलब रहता है।''

इसी प्रकार भारतीय विधि आयोग (ओल्ड कमीशन ऑफ इन्डिया) ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि-''पेंचदार मामलों के अनुसंधान में खास तौर से विलंब किया जाता है और गुण की दृष्टि से भी यह हमेशा घटिया किस्म का होता है। अनुसंधान अफसर प्रर्याप्त प्रशिक्षित नहीं रहते है। आयोग ने यह सुझाव दिया कि यथासंभव एक ही अफसर अपराध अनुसंधान कार्य एक निरीक्षक या उपाधीक्षक जैसे सीनियर अफसर अपने हाथ में ले लें।''

पुलिस कमीशन, 1961 ने अपने रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया है कि-''पुलिस अधीक्षक यह कोशिश रखें कि पेशेवर डकैतों और हत्याओं के सभी मामलों तथा पेशेवर ठगी के कुछ मामलों के अनुसंधान कार्य का भी स्वयं देख-रेख करें।''

उपाध्यक्ष महोदय, आज क्या हो रहा है? आज क्या होता है? आज थाने में जो सबसे गया-गुजरा दारोगा होता है उसी को केस देखने के लिए दे दिया जाता है और थाने में जैसे ही कोई केस आया, दारोगा जी का आदमी कल्प्रीट के पारा जाता है, पहले उसको बुलाया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस कमिशन ने अपने प्रतिवेदन (196) में यह सुझाव दिया है कि-''सबसे महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि लोग पुलिस के बारे में क्या कहते हैं। जनता की आवाज़ ईश्वर की आवाज है। हर पुलिस कर्मी की ऐसी चेष्टा करनी होगी वह फोर्स और राज्य का सच्चा प्रतिनिधि माना जाय और कोई उस पर उंगली न उठाए। पुलिस की एक गलती अखबार का मामला बन जाती है और तेजी से जग-जाहिर हो जाता है और पूरे फोर्स के मुंह पर कालिख पोत देता है। उस एक व्यक्ति की चूक पूरे फोर्स और सरकार की चूक मानी जाती है। कमीशन के विचार से फोर्स का हर एक सदस्य उत्साहपूर्वक फोर्स की ख्याति बचाए और प्रचार या सस्ती वाहवाही के जरिये नहीं, बल्कि कड़ी मिहनत से, ईमानदारी के साथ पक्का काम कर के

जनता का सद्भाव अर्जित करे।''

उपाध्यक्ष महोदय, आज थाने की क्या स्थिति है? हम लोग यहां दोनों पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। आज कोई दारोगा, इसी सदन के दोनों पक्षों के विधायकों के साथ क्या घटना हुई? बालूमाथ के माननीय सदस्य और भोला बाबू के साथ दुर्व्यवहार हुआ। आज आप या हम एक साधारण व्यक्ति बन कर थाने में जांच एफ०आई०आर० करने के लिए तो जानते हैं वहां क्या होगा? थाने में तो आज दारोगा एस०पी० बने हुए हैं। एक बात और कह रहा हूं। आज सभी राजनीतिक बंधुओं को सोचना होगा। अगर थानेदार पर आप बहुत ज्यादा कार्रवाई करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं तो जो गुण्डा तत्व हैं उससे वह दारोगा आपको मरवाने के फेर में रहेगा। एफ०आई०आर० कराने जाइए तो सबसे पहले वहां का मुंशी रिश्वत मांगेगा। आज इस तरह के दारोगा यहां हैं। कई दारोगा की दोस्ती गुण्डा तत्वों के साथ है। आज राजनीतिज्ञों की हत्या, पत्रकारों की हत्या की कार्रवाई हो रही है। हमारे जानते एक घटना हमारे जमशेदपुर में घटी है, चाईबासा के पत्रकार के साथ घटना घटी है क्योंकि उन्होंने इन तत्वों के खिलाफ लिखा था। इस तरह से आज जनसाधारण कैसे रहेंगे?

आज पुलिस के पदाधिकारी क्षेत्र में निरंकुश हो कर काम कर रहे हैं और इस विभाग के आफिसर यहां पटना में बैठे रहते हैं। इसी को दारोगा राज कहते हैं। आज की स्थिति जंगल राज की तरह हो गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में कितने ही ऐसे लोग हैं, हमारे बगल में माननीय सदस्य श्री फाल्गुनी जी बैठे हुए हैं, संकटेश्वर बाबू बैठे हुए हैं, कई महिला माननीय सदस्या हैं। आपके पक्ष में भी ऐसी विधायिका हैं, हमारे रामाधार बाबू भी हैं। हमलोगों को बॉडी-गार्ड दिया जाता है लेकिन उसका पता ही नहीं रहता है, वह कब आता है, कब चला जाता है, पता नहीं रहता है। बीस-बीस दिन गायब रह जाता है और चला आता है लेकिन पूरा

वेतन मिल जाता है। जब मैंने इस बावत खबर किया मेजर को तो मेजर ने वेतन दे दिया और परसेंटेज मेजर लेते हैं, ऐसी जानकारी है। आज किसी को अपी-वर्दी लेने के लिए, कंबल लेने के लिए, वेतन-भत्ता लेने के लिए दस प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है। एस०पी० के यहां रीडर भी पैसे देने की परंपरा है।

(व्यवधान)

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, अभी बीस मिनट नहीं हुआ है। थोड़ा सा और समय दिया जाए। महोदय, थोड़ा सा समय और ले रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार में जेलों की क्या स्थिति है ? सेंट्रल जेलों की संख्या 8 है, कुल जेलों की संख्या 82 है जिसमें सब-जेलों की संख्या 44 है। यहां कैदियों के रहने की कुल क्षमता 25800 है लेकिन वर्तमान में इन जेलों में 43000 कैदी रह रहे हैं। मुख्य मंत्री जी के गृह जिले गोपालगंज के जेल की क्षमता 60 है जिसमें 305 कैदी रह रहे हैं।

महोदय, सप्तम् वित्त आयोग द्वारा बिहार में जेलों के विस्तार का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। राशि आवंटित की गयी लेकिन अभी तक जमीन अर्जित नहीं की गयी है। भवन निर्माण विभाग के पास पैसा रखा हुआ है। वह राशि कहाँ गयी, पता नहीं।

महोदय, 4 हजार कक्षपालों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र 982 होना चाहिए किन्तु अभी मात्र 54 असिस्टेंट जेलर हैं। महोदय, जेलों से कैदियों के पलायन की विश्व इतिहास की सबसे बड़ी घटना बिहार में हुई। तेनुघाट सब-जेल से एक साथ 107 कैदी भाग गये थे। उस समय उनकी सुरक्षा के लिये मात्र चार सिपाही थे। महोदय, 1997-98 में करीब 150 बंदी जेलों में चिकित्सा के अभाव में मर गये। महोदय, जेल में बड़े अपराधी जेल प्रशासन के संरक्षण में छोटे अपराधियों का शोषण करते हैं। महोदय, अब तो जेलों में

गाँजा, भाँग, दारू, बीड़ी, सिगरेट और हशीश भी बेचा जाता है।

महोदय, खुद यहाँ बेऊर जेल में 50 प्रतिशत बन्दी स्टोभ पर खाना बनाते हैं। महोदय, बिहार के जेलों के सम्बन्ध में सबसे सनसनी खेज और रोचक तथ्य यह है कि भागलपुर सेन्ट्रल जेल में 16 आजीवन कारावास के बंदियों को छोड़ दिया गया। श्री श्याम मोहन प्रसाद जब भागलपुर में अधीक्षक थे तो 35 ऐसे ही बंदियों को छोड़ा गया और अभी ये सहायक कारा अधीक्षक हैं। श्री चन्द्रेश्वर मिश्र, तत्कालीन अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर ने 10 ऐसे ही बंदियों को छोड़ दिया था। श्री वी०एम० मुण्डा, वर्त्तमान में सहायक कारा महानिरीक्षण ने ऐसे ही 3 बंदियों को छोड़ दिया और आश्चर्य यह है कि मुण्डा जी श्री डी०पी० सिंह के केस की जाँच कर रहे हैं। महोदय, श्री ए०के० चौधरी ने 13 ऐसे ही बंदियों को छोड़ा था। श्री कृष्ण रविदास ने मुजफ्फरपुर में 21 बंदियों को छोड़ दिया। महोदय, क्यों नहीं इन सारे मामलों की जाँच हो रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा-सा अपने क्षेत्र जमशेदपुर का समस्याओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। महोदय, आज जमशेदपुर की जो स्थिति है, दो साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, हालांकि उस समय भी यही सरकार थी लेकिन आज वहाँ पर महिलाओं का चलना कठिन हो गया है। आज वहां शाम को ही गाड़ी छीन लिया जाता है। वहाँ पर दारोगा तो एस०पी० जैसा है और एस०पी० तो घर से निकलते ही नहीं हैं, शायद वे ब्यूरोक्रेट हैं जिसके कारण ऐसा हो।

महोदय, मैं एक मिसाल के रूप में बताना चाहता हूँ कि 14 जून को जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में विनय कुमार नाम का एक लड़का मोटरसाईकिल से जा रहा था, उसका एक रिक्शा से मामूली एक्सीडेंट हो गया। दोनों में मामला रफा-दफा भी हो गया लेकिन थाना प्रभारी ने उसको थाना में बैठा लिया। उस लड़के ने कहा कि हम जानकर धक्का नहीं मारा है, रिक्शा

वाले ने भी अचानक गलत ढंग से रिक्शा को घुमा दिया था, अगर केस ही करना चाहते हैं तो केस कर दीजिए। लेकिन उसको फिर भी नहीं छोड़ा गया, पाँच हजार रुपया माँगा गया। मैंने उस समय ऐक्टिंग डी०एस०पी०, श्रीमती शर्मा से कहा तो उन्होंने भी दूरभाष पर कहा कि मामूली केस है, उस लड़के की जमानत पर छोड़ दें लेकिन उसको नहीं छोड़ा गया। मैंने फिर डी०एस०पी० से कहा तब जब उन्होंने टेलिफोन पर कहा तो जमानत पर उसको छोड़ा गया। एम०भी०आई० का रिपोर्ट आ जाने के बाद भी मोटरसाईकिल नहीं छोड़ा गया, पाँच हजार रुपया माँगा गया। फिर मैंने आरक्षी अधीक्षक से कहा तो मोटरसाईकिल दिया गया, बागवेड़ा थाना-प्रभारी उसके घर पर भी गया।

महोदय, एक गरीब नाई है, महावीर ठाकुर, उसको टेल्को के थाना प्रभारी ने आजाद मार्केट में उस नाई को खुद पीटा और अपने अंगरक्षक से भी पिटवाया। उस नाई को थाना प्रभारी ने इसलिए पीटा कि वह सुबह में उनके घर पर दाढ़ी बनाने नहीं गया था, नाई ने कहा कि हुजूर, हम सैलून छोड़कर कैसे घर पर दाढ़ी बनाने जा सकते हैं। इसी पर उसको खूब पीटा गया।

महोदय, वहाँ एक इंस्पेक्टर है, दिवाकर सिंह, वह जमशेदपुर में 10 साल से भी ज्यादा दिनों से है। अभी वह नेरकोटिक्स में है और खूब हशीश बेचवा रहा है। महोदय, उसको जमशेदपुर में 10 कीता मकान है, बाँकाक में भी समाहरणालय के निकट एक मकान है। महोदय, ऐसे अफसर जो एक जगह पर 10-15 वर्षों से जमे हैं, उनकी राजनीतिक सिफारिश नहीं सुनी जाय, उनको वहाँ से हटाइये। महोदय, छोटानागपुर में ही आज सभी लोग जाना चाहते हैं। अगर पुलिस में वहाँ जगह नहीं है तो सी०आई०डी० में चले जाते हैं, अगर सी०आई०डी० में नहीं है तो विशेष शाखों में चले जायेगें। महोदय, सी०आई०डी० में वहाँ पर नियुक्ति नहीं करके भेजते हैं, वहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर भेजते हैं। लोग वहाँ पर 5-6 साल से हैं और जब पटना अपने वेतन के

लिये आते हैं तो उनको रेलवे वारन्ट नहीं दिया जाता है। पुलिस के साथ भी यही कठिनाई है। महोदय, मैं चाहूँगा कि पुलिस को सारी सुविधायें दी जायें ताकि उनकी नैतिकता बनी रहे।

महोदय, अगर व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आज जो हत्यायें और राजनीतिक हत्यायें हो रही हैं, वह बढ़ती जायेंगी और समस्या का निदान नहीं हो सकेगा।

उपाध्यक्ष - माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मृगेन्द्र प्रताप सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक पुलिस की राजनीतिकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण दोनों का समन्वय नहीं हटेगा, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है। धन्यवाद।

श्री मो0 नेमातुल्लाह - उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और कटौती प्रस्ताव के विरोध में। महोदय, सोचता हूँ कहां से शुरू करूं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की हत्या से या अभी जो घटनायें घटी हैं। आजादी के बाद से जो घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ और इसको किन लोगों ने शुरू किया, हत्यायें किस तरह से होती हैं, जो भी हत्या होती है, वह क्यों होती है। जब अहिंसा के पुजारी को जिन्होंने पूरे देश में अहिंसा का प्रचार कर देश को आजादी दिलायी, उनको भी लोगों ने नहीं बख्सा तो आज आम आदमी की जान-माल का खतरा किन लोगों के जरिये बढ़ गया है, यह सर्व-विदित है। कौन सी राजनीति देश में चलाना चाहते हैं, इसके पीछे एक गहरी साजिश है, इस पर हम सभी लोगों को बैठकर विचार करना होगा। सिर्फ पुलिस प्रशासन के मथे दोष दे करके और उनको डिमोर्लाईज करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारे पुलिस पदाधिकारी दोषी है, उसमें कुछ पुलिस पदाधिकारी निष्क्रिय है, कुछ पुलिस पदाधिकारी गैर-जिम्मेवार हैं लेकिन सारे

पुलिस पदाधिकारी को दोषी ठहराना, उनको डिमोर्लाईज करना किन लोगों का काम है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके पीछे भी किन लोगों का हाथ है, इसके विषय पर भी यहां बात होनी चाहिए। बहुत लोगों ने डाटा दिया, अभी माननीय सदस्य बिहार के बारे में डाटा दे रहे थे लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश के डाटा को देखते हैं, महाराष्ट्र के डाटा को देखते हैं, राजस्थान के डाटा को देखते हैं, दिल्ली प्रदेश के डाटा को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां जो लोग शासन चला रहे हैं, वे अपने गिरेवान में झांक कर देंखें। आज उन्हीं के लोग एलान करते हैं, उन्हीं की सरकार है और आपके ही लीडर श्री के.एल.शर्मा जी कहते हैं कि यहां का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, हम उस वक्त तक अन्य ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक हमारे यहां विधि-व्यवस्था ठीक न हो जाय, महोदय, ये कौन लोग कर रहे हैं। प्रधान मंत्री के अधीन जब जम्मू-काश्मीर था तो वहां पर आतंकवाद काबू में था लेकिन जब से आडवाणी जी को चार्ज मिला है, लगता है कि वे सभी आर.एस.एस. को वहां भेज दिये हैं, वहां रोज-ब-रोज आज कत्ले-आम हो रहा है, दिनों-दिन खून खराबा बढ़ता जा रहा है, तथ्य को आप झुठलाईये नहीं। महोदय, आज प्रधानमंत्री लखनऊ गये हैं और वहां आज क्या हो रहा है। वे डाटा दे रहे थे तो हम कुछ नहीं बोल रहे थे।

श्री सुशील कुमार मोदी - उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन पहले तय कर ले कि पूरे देश के लॉ एंड आर्डर पर यहां चर्चा करना है या बिहार पर ही चर्चा करना है। अगर पूरे देश के लॉ एंड आर्डर पर चर्चा करना है तो हम भी बोल सकते हैं इसलिए हमारा आग्रह है कि केवल बिहार तक में ही चर्चा को सीमित रखा जाय चूंकि आज बिहार सरकार के गृह विभाग के ऊपर ही चर्चा हो रही है। दूसरे राज्यों के बारे में बात यहां उठाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री विश्वनाथ वर्मा - उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि आडवाणी जी ने आर०एस०एस० भेजकर वहां पर कत्तलेआम करवाये। इसको

प्रोसिडिंग से निकलवाया जाय।

उपाध्यक्ष - अगर यह सब आया है तो उसे प्रोसिडिंग से निकाल दिया जाय।

श्री मो0 नेमतुल्लाह - उपाध्यक्ष महोदय, हम दूसरे राज्यों के साथ तुलना कर रहे हैं। अभी हमारे पास इसका डाटा भी है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में. ....

श्री जगदानंद सिंह - महोदय, हमारा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आज सदन में बहुत ही गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य श्री मृगेन्द्र बाबू जब बोल रहे थे तो पूरा सत्ता पक्ष के लोग उसे शांतिपूर्वक सुना। हम चाहेंगे कि जब सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं तो विपक्ष भी उसको शांतिपूर्वक सुने।

श्री सुशील कुमार मोदी - चर्चा हो रही है बिहार पर और बोलेंगे उत्तर प्रदेश पर।

श्री मो0 नेमातुल्लाह - उपाध्यक्ष महोदय, आप सदन की एक कमिटी बना दीजिए और कमिटी से जांच करवा लीजिये कि इसमें आर०एस०एस० वालों का हाथ है या नहीं ?

उपाध्यक्ष - सभी माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के इनसे हमारा आग्रह है कि अभी बहुत ही महत्वपूर्ण गृह विभाग पर चर्चा चल रही है। शांति व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, इसलिए सब लोग इसको गम्भीरता से लीजिए। बिहार के अन्दर में ही बोलिये।

श्री मो0 नेमातुल्लाह - उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे राज्य का आंकड़ा दे रहा हूँ। महोदय, जिस तरह से बिहार में पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था के लिए जो काम किया है उसकी भी हम चाहेंगे कि प्रशंसा होनी चाहिए। महोदय, 1990 के बाद जिस तरह से बिहार में दंगा फसाद हुआ, आडवाणी जी रथ लेकर आये तो दंगा फसाद हुआ उसके बाद पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से

मुस्तैदी से उसको रोकने का काम किया उसके लिए पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए। उस समय श्री लालू प्रसाद जी की सरकार थी उन्होंने दंगा को कंट्रोल किया, पुरे देश में बिहार दंगा मुक्त रहा और श्रीमती राबड़ी देवी की भी सरकार ने साबित कर दिया कि बिहार एक दंगामुक्त राज्य है। महोदय, दूसरे राज्यों को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश को ही लीजिए।

उपाध्यक्ष - माननीय सदस्य, बार-बार आप उत्तर प्रदेश की घटना की बात कीजियेगा तो हाउस में शांति नहीं रहेगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष - आपसे आग्रह किया गया है कि बिहार के संदर्भ में बोलिये।

श्री मो0 नेमतुल्लाह - महोदय, हम एक कंपरिजन करना चाहते हैं, हम उनको जबाव देना चाहते हैं, इसलिए महोदय, उन लोगों को बैठाया जाए। आप प्रोटेक्शन दीजिए महोदय।

उपाध्यक्ष - आप अनुमति दे रहे हैं।

श्री जगदानन्द सिंह - हाउस को ऑर्डर में किया जाए हुजूर, इस तरह से तो नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री रामाधार सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, बंगला देश के बारे में हम कहेंगे तो अच्छा लगेगा?

उपाध्यक्ष - बैठिये।

श्री मो0 नेमतुल्लाह - आज लगेगा इन लोगों को क्योंकि हम सच बाते कहते हैं। सी.बी.आई. की मांग ये लोग करते हैं। सी.बी.आई. की हॉनेस्टी-डिग्निटी आज डायवर्ट हो गई है, उसका भी रेकर्ड है हमारे पास महोदय। इसकी भी चर्चा हम करना चाहते हैं। बिहार की पुलिस और सी.बी.आई. की पुलिस में

कोई अन्तर नहीं है और इससे घटिया काम उसने किया है। जब बी.जे.पी. की पार्टी को सी.बी.आई. फंड दिलवाने का काम करती है-इसका भी हमारे पास प्रूफ है महोदय, इसकी भी जांच होनी चाहिए और पशुपालन घोटाला के थ्रू पार्टी फंड में भाजपा को कई करोड़ रुपया दिया गया महोदय। यह हकीकत है, इसका प्रूफ है हमारे पास।

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि जो सीमित साधन है प्रशासन में, उसमें जिस तरह से वह काम है उसकी सराहना होनी चाहिए और मैं कह रहा था कि राबड़ी जी की सरकार में, जो लालू जी की सरकार के नक्शे-कदम पर चलना चाहा और बिहार राज्य को दंगा-मुक्त राज्य बनाया महोदय।

महोदय, आज बिहार में लालू यादव.....

श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव - उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह कहे जा रहे हैं कि आडवाणी जी की रथ यात्रा में दंगा हुआ तो हम जानना चाहते हैं कि बिहार से जब आडवानी जी का रथ गुजर रहा था तो कहां-कहां दंगा हुआ और दूसरा जो इन्होंने कहा कि सी.बी.आई. ने इसको चंदा दिलवाया तो इसको भी रखने का काम करें, नहीं तो यहां गलतबयानी बंद करें, अन्यथा इसको प्रौसिंडिंग्स से बाहर किया जाए।

मो0 नेमतुल्लाह - महोदय, इसकी भी जांच के लिए कमिटी बना दी जाए, कैसे दिया है उसके सामने प्रस्तुत करेंगे, कह दिया है जांच कमिटी बनाइये।

(व्यवधान)

और मत खोलवाइये, नहीं तो और भी बोल देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष - माननीय सदस्य, आपका समय अब समाप्त हो रहा है।

मो0 नेमतुल्लाह - अब बकस रहे हैं आपको। महोदय, प्रत्येक थाना में उर्दू जानकार एक पदाधिकारी को बहाल करने का जो इस सरकार ने किया है, तो हम चाहते हैं कि इसकी प्रक्रिया शुरू करके हर थाना में एक उर्दू जानकार पुलिस पदाधिकारी को बहाल किया जाए। (हरी बत्ती) उपाध्यक्ष महोदय, आपने हरी बत्ती जला दी है, हमको समय का ख्याल है लेकिन मुझे कुछ बाते और कहंनी है।

श्री शिवनाथ वर्मा - उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य धमकी देते हैं कि बोल देंगे, बोल देंगे, क्या बोल देंगे-बोलिये। (हँसी)।

श्री मो0 नेमतुल्लाह - महोदय, कूपन हमलोग भी दे देते हैं बिहार भवन में किसी कर्मचारी को कटाने के लिए ....

उपाध्यक्ष - यह प्रसंग न ही उठाया जाय तो अच्छा है।

श्री मो0 नेमतुल्लाह - महोदय, पूरे बिहार में पुलिस रेक्रूटिंग कमिटी है। महोदय, यह बिहार सरकार का रूल है कि उस कमिटी में अनुसूचित जाति के अनूसूचित जनजाति के और अल्पसंख्यक समुदाय के एक-एक आदमी को मेम्बर के रूप में रखना है। महोदय, उस रेक्रूटिंग बोर्ड मे, महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस पुलिस रिक्रूटिंग बोर्ड में खानापूरी करने के लिए हर समुदाय के एक-एक आदमी को रख दिया जाता है। महोदय, उस बोर्ड में डी.आई.जी. रहते हैं, आई.जी. रहते हैं, लेकिन उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के या अनुसूचित जाति/जनजाति के डी.एस.पी. को रख दिया जाता है। क्या वे उसकी वकालत कर सकेंगे, उसके बारे में कुछ कह सकेंगे? इसीलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि पुलिस रिक्रूटिंग कमिटी में इन समुदायों के भी उसी स्तर के पदाधिकारियों को रखा जाय।

उपाध्यक्ष - माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया। माननीय सदस्य

श्री फुरकान अंसारी।

श्री मो0 नेमतुल्लाह - उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैंने अपनी बातों को पूरी तरह रखा भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि समय समाप्त हो गया। महोदय, मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दीजिये। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि......

उपाध्यक्ष - माननीय सदस्य आप मुख्य सचेतक हैं सत्तारूढ़ दल के, आप अगर अधिक और बोलेंगे तो माननीय मंत्री को जो समय हम देना चाहते हैं, सदन भी चाहता है, वह कट जायेगा।

श्री मो0 नेमतुल्लाह - महोदय, मुझे थोड़ा समय और दिया जाय।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष - माननीय सदस्य, आप सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक हैं, आपको सदन की परिपाटी माननी चाहिए। आपका समय समाप्त हो गया है, आप नहीं मानेंगे तो जितना बोलना चाहते हैं, बोलिये।

श्री मो0 नेमतुल्लाह - महोदय, आज हर थाने में जीप मुहैया नहीं हो रहा है। हमारा जो पुलिस प्रशासन है उसके पास सोफिस्टिकेटेड आर्म्स नहीं है इसलिए उनको दिक्कत होती है जो टेरोरिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं उनसे लड़ने में। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि हर थाने में जीप मुहैया करायी जाय, सोफिस्टिकेटेड आर्म्स मुहैया कराया जाय और जो सिक्रेट फण्ड है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है, उसको और बढ़ाया जाय ताकि जो पुलिस प्रशासन को दिक्कत होती है, अपराधियों को पकड़ने में, अपराधियों तक पहुँचने में, उसमें उनको प्रोत्साहन देकर वहां तक पुहँचाया जा सके। महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

उपाध्यक्ष - माननीय सदस्य श्री फुरकान अंसारी।

श्री श्रवण कुमार - उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ। महोदय, माननीय सदस्य नेमतुल्लाह जी का समाचार पत्रों में बयान छपा था कि मेरे जान माल पर खतरा बना हुआ है। उस बिन्दु पर माननीय सदस्य ने कुछ नहीं कहा, जिला पदाधिकारी ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बारे में उनको सदन को बताना चाहिए कि खतरा उन पर है या समाप्त हो गया। उस समय की विधि-व्यवस्था इनको कैसी लगी?

उपाध्यक्ष - माननीय सदस्य श्रवण कुमार जी, यह कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ नियम-कानून पढ़िये, कुछ किताबें पढ़िए कि व्यवस्था किस-किस विषय पर होती है, नहीं तो इस तरह से सदन में अव्यवस्था फैल रही है। यह बात आपको अपने भाषण के क्रम में कहनी चाहिए।

श्री फुरकान अंसारी - उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने 1993-99 वर्ष के लिये जो बजट प्रस्तुत किया है उस पर बोलने के लिये मैं खड़ा हूं। सबसे पहले मैं सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि डी.जी.पी. के पद पर एक अच्छे औफिसर को इन्होंने पदस्थापित किया है। इसलिए मैं सबसे पहले बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने एक ऐसे पदाधिकारी को डी.जी.पी. के पद पर नियुक्त किया है जो न्यूटरल औफिसर हैं। ये हमलोगों के जमाने के औफिसर रहे हैं लेकिन मैं एक आग्रह करूंगा कि इनको पौलिटिकलाइज करने की आप लोग कोशिश नहीं करें। उपाध्यक्ष महोदय, योजना मद में और गैर योजना मद में जो बजट पेश किया गया है उसमें योजना मद में 1993-99 के लिये 37 करोड़ 39 लाख रुपया योजना मद में और गैर योजना मद में 12 अरब, 3 करोड़ 93 लाख रुपये का मांग प्रस्तुत किया है। सरकार ने जिन योजनाओं की घोषणा की है उसमें उन्होंने प्रत्येक थाना में एक-एक उर्दू नोर्डिंग अधिकारी को भी देने की घोषणा की। जब इसके लिये योजना मद में राशि की बढ़ोत्तरी नहीं की गई तो कहां से ये दारोगा को बहाल करेंगे, अधिकारियों को कहां से बहाल करेंगे। सरकार

जब जवाब देगी तो मैं सरकार से इस विषय में जानना चाहूंगा कि आपने सिर्फ धोका देने का काम किया है या अल्पसंख्यकों को सही माने में कुछ करने जा रहे हैं। दूसरी बात है, उपाध्यक्ष महोदय, कि क्राइम के मामले में जो दूसरे-दूसरे राज्यों का यहां पर आंकड़ा है उसमें बिहार का इस मामले में पूरे भारतवर्ष में दूसरा नम्बर है। इसलिए अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, आडवाणी जी के बारे में और किसी दूसरे राज्य के बारे में तो आंकड़े और तुल्नात्मक दृष्टिकोण से तो बोलना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि गुजरात के क्राइम के जो आंकड़े है उसे अगर तुल्नात्मक दृष्टि से देखा जाये तो बंगाल का नम्बर आता है। गुजरात, उड़िसा, यू.पी. में क्राइम के जो प्रतिशत हैं वे काफी अधिक हैं। इसलिए मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं। बिहार इस मामले में बहुत हद तक बेहतर है।

(व्यवधान)

पूरे भारतवर्ष के आंकड़े को आप देखेंगे तो उस अनुपात में तो बिहार अच्छा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े आज अखबारों के माध्यम से हमको मिलते हैं, भारतवर्ष के जो आंकड़े है उसे मैं बताना चाहता हूं।

श्री शिवनाथ वर्मा - बिहार में पांच विधायकों की हत्या हो गई है, दूसरे राज्य में कितने विधायकों की हत्या हुई है यह आप बता सकते हैं।

श्री फुरकान अंसारी - उपाध्यक्ष महोदय, इस राज्य में राजनीतिक हत्या का एक सिलसिला चल पड़ा है। 1995 में जहां राजनीतिक हत्या 36 थी वह 1997 में 41 है और 1993 में 48 पर आकर खड़ा है और यह साल अभी बाकी है।

राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला बढ़ रहा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि क्राईम बढ़ रहा है। आज छोटानागपुर और संथालपरगना

में लालखंडी, आई०पी०एफ० के द्वारा जो हत्यायें हो रही है, उसको रोक नहीं सकती है यह सरकार, सरकार इसलिए नहीं रोक सकती है कि जब तक इसकी गहराई में नहीं जायेगे, आखिर इसका क्या कारण है, यह क्यों हो रहा है, जब तक इस गहराई में नहीं जायेंगे तब तक यह हत्यायें बंद नहीं हो सकती हैं। हमारे क्षेत्र में भी लालखंडी का प्रकोप है, वहां लाल खंडी सर उठा रहा है, मैं वहां गया था और हमने लालखंडी से बात किया तो यही मसला सामने आता है, यानी समस्या देखते हैं कि जमीन का विवाद है तो कहीं घर का विवाद है, कहीं महाजनी विवाद है, ये सारे विवाद उजागर होते हैं और हत्यायें होती है। उपाध्यक्ष महोदय, एक विवाद और भी है जो जमीन का केस है अनुमंडल स्तर पर राज्य स्तर पर, वह कहीं पांच साल से तो कहीं दस साल से कहीं १५ सालों से उलझा हुआ है। एक गरीब आदमी कहता है कि मुझे केस में कोर्ट से न्याय नहीं मिलने वाला है, इन बातों को देखने के बाद जब वह परेशान हो जाता है तो इस तरह के क्राईम करने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए मैं सरकार को सलाह देना चाहता हूं कि लालखंडी या इस तरह के जो क्राईम संथाल परगना और छोटानागपुर में हो रहे हैं, उसके गहराई में जाईये और जो विवाद भूमि का है उसको हल करने की कोशिश कीजिए। आप वहां पर कैम्प कीजिए और कैम्प करके उन लोगों के मसले पर हल कीजिए, जमीन का जो लफड़ा है उसे हल कीजिए। यह मेरी सलाह है।

तीसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों का दल जो नेक सलाह है वह सरकार को देंगे और जो सरकार की खराबी है उसे उजागर करेंगे हमलोगों का एक चरित्र को देखने की कोशिश कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज अच्छे पुलिस ऑफिसर का मनोबल गिरा है, इस राज्य में पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग उसके कार्यक्षमता के आधार पर करेंगे तभी क्राईम रूकेगा। जात-पात के आधार पर किसी अधिकारी की

पोस्टिंग करेंगे तो कभी भी क्राईम नहीं रूकेगा। इसलिए मेरा कहना है कि बिहार सरकार यदि चाहती है ईमानदारी से क्राईम को रोकना चाहती है तो जो अच्छे और सक्षम पदाधिकारी हैं, उसकी पोस्टिंग आप कीजिए, पोस्टिंग जाति और धर्म के आधार पर नहीं कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष के दूसरे राज्यों में आप देखेंगे तो वहां प्रत्येक साल हर पुलिस ऑफिसर को फिटनेश सर्टीफीकेट अप्रील महीने में वहां के एस०पी० को भेजा जाता है। सारे पुलिस ऑफिसर से फिटनेश सर्टीफीकेट लेते हैं, यदि वह फिट है तभी कन्टीन्यूस करता है, यदिन फिट नहीं है तो फिल्ड में नहीं रखा जाता है। इस राज्य में एक-एक हवलदार डेढ़-डेढ़ क्वीन्टल का और एक-एक दारोगा एक-एक क्वीन्टल का मिलेगा, जब कोई चोर सामान लेकर भागता है तो वह हवलदार और दारोगा दौड़ नहीं सकता है चूंकि ये डेढ़ क्वीन्टल और एक क्वीन्टल से कम के नहीं हैं। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि बिहार राज्य के पुलिस ऑफिसर से भी प्रत्येक साल मार्च महीने के बाद फिनानशियल इयर के खत्म होने के बाद, अप्रील महीना में फिटनेश स्र्टीफीकेट लेना चाहिए, जब तक फिटनेश सर्टीफीकेट नहीं लें तब तक उनकी पोस्टिंग फिल्ड में नहीं किया जाए। अफटनेश है तो वैसे अधिकारी को फिल्ड में भेजा जाए। मेरी यह एक नेक सलाह है सरकार को।

उपाध्यक्ष - अब आप समाप्त करें। समाप्त कैसे करें, इन्टरमैन आपके दल ने किया है।

उपाध्यक्ष - आपको सहयोग दिया है।

श्री फुरकान अंसारी - प्रत्येक थाना में अल्प-संख्यक अधिकारी देने की बात कही गई है-अल्प-संख्यक को धोखा देने की कोशिश मत कीजिये। आपने माइन्योरिटी फाईनेन्स कॉरपोरेशन और अल्प-संख्यक विकास विभाग को होम डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया है-क्या बिडम्बना है? क्या इससे आप अल्प-संख्यक का विकास कर सकते हैं? मेरा सुझाव है, जगदा बाबू जरा

ध्यान दीजिये, अगल से इसके लिये विभाग का गठन कीजिये, अगर सम्भव नहीं हुआ तो इसको कल्याण विभाग के साथ जोड़ दीजिये ताकि उन लोगों का विकास हो सके यदि आपकी नीयत साफ है तो, नीयत साफ नहीं है, एम० और वाई० का कम्बीनेशन लेकर चलना नहीं हैं, केवल वाई० को लेकर चलियेगा, एम० को छोड़ दीजियेगा तो आप धोखा खाइयेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ। आप इन बातों को ठंडे दिमाग से सोच लीजिये, इससे भागिये नहीं।

दूसरी बात, आज थाना का जिला स्तर पर हम महीना में क्राईम का मिटिंग होती है, आप किस बात की क्राईम की मिटिंग करते हैं? एस०पी० साहब को हाजरी दीजिये और माल डाऊन कर दीजिये। यदि क्राईम की मिटिंग मुस्तैदी के साथ हो तो क्राईम क्यों नहीं रूकेगा? अच्छे ऑफिसर होंगे तो क्राईम क्यों नहीं रूकेगा। यही सक्षम अधिकारी कांग्रेस के समय थे, उस समय क्राईम नहीं होता था–आज क्राईम क्यों इतना बढ़ रहा है? आपकी नीयत साफ नहीं हैं, आपके अधिकारी बे-लगाम हो गये हैं, पोस्टींग जो आप करते हैं जात-पात के आधार पर करते है।

उपाध्यक्ष - अब आप समाप्त करे। मुझे दस दलों को बुलाना पड़ता है।

श्री फुरकान अंसारी - उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कितना चुभने वाला है, इनका जो विशेष शाखा है, स्पेशल ब्रांच है उसमें एस०पी० से ऊपर आज तक किसी भी अल्प-संख्यक अधिकारी की पोस्टींग नहीं की गई है। क्या आपको अल्प-संख्यक पर आपको डाऊट है? क्यों नहीं आप वहां पोस्टींग करते हैं? क्या तकलीफ है? अगर शक है तो बतलाइये कि क्या शक है? एस०पी० से ऊपर अल्प-संख्यक अधिकारी की आपने पोस्टींग नहीं की, यह आपात्तिजनक बात है।

श्री नेमतुल्लाह - पहली मरतबा माननीय श्री लालू प्रसाद की सरकार ने डी०एस०पी०, इन्टेलिजेंस में अल्प-संख्यक की बहाली वर्ष १९९२ में की थी, इससे पहले इन्सपेक्टर तक की बहाली नहीं हुई थी।

श्री फुरकान अंसारी – महोदय, ९९ प्रतिशत पुलिस आज शराब पीता है। एक घटना घटती है हमारे निर्वाचन क्षेत्र दुमका जिला के जामताड़ा में, ज़ब में रेलवे क्रासिंग के पास पहुंचा तो हमारे तीन आदमी को पुलिस पकड़े हुई थी, मैं वहां पर रूका और पूछा क्या बात है? तो बताया, हुजूर, ये लोग शराब पिये हुये हैं, सही में वे लोग पिये हुये थें, लेकिन जो पुलिस यह बोल रहे थें, उनके मुंह से शराब की महक इतनी आ रही थी जिससे पता चलता था कि उन लोगों से भी ज्यादा पिये हुये हैं-शराब पीने वाला शराब पीने वालों को रोक नहीं सकता है, इसको आपको देखना पड़ेगा।

दूसरी बात ये पुलिस वाले जो मोटर-साईकिल चलाते हैं, उस पर गाड़ी का नम्बर नहीं होता है, बिना नम्बर की ही उनकी गाड़ी रहती है, क्या उनके लिये मोटर भैकिल एक्ट लागू नहीं होता है? वे अपने गाड़ी पर नम्बर क्यों नहीं लगाते हैं ? दूसरी बात जब पुलिस अधिकारी रात में, पैट्रोलिंग गस्ती में निकलते हैं तो वे रोड पर निकलते हैं, मैंन रोड पर निकलते है-मेन रोड पर निकलने का क्या कारण है? क्रिमनल मेन रोड से जायेगा? क्या डकैती, मेंन रोड में डकैती करने जायगा, यह सोचने की बात है लेकिन देखियेगा रात में किसी रास्ते से गुजरिये मेन रोड में गाड़ी लेकर पुलिस वाले खड़े हैं और हर ट्रक वाले को रोक कर पैसे की वसूली करते हैं। यदि आप पूछेंगे कि ट्रक क्यों रोके तो वे बोलेंगे इसमें दो नंबर का माल बा-आप कहेंगे कि आपको कैसे मालूम हो गया कि दो नंबर का माल लेकर जा रहे हैं, कैसे मालूम हो गया? क्रिमनल रिवौलभर लेकर चले जा रहे हैं यह नजर नहीं आता हैं, यह आपकी पुलिस की खराबी है, ये पुलिस वाले हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं खासकर अधिकारी दीर्धा में जो अधिकारी बैठे हैं उनको कहना चाहता हूं कि यह उनकी खराबी है, आप उसको सुधारिये। मैं कोई क्रीटसाईज नहीं कर रहा हूँ। उसको सुधारिये, नहीं सुधारियेगा तो बिहार जल जायेगा और क्राईम का सबसे बड़ा अड्डा बन जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी ये लोग कह रहे थे दंगा के बारे में कि इस देश में दंगा नहीं हो रहा है, वह होगा कैसे? दंगा करने

वाले जाकर बैठ गए हैं कुर्सी पर, दंगा कौन करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग दंगा की बात कर रहे थे, दंगाई लोग सत्तारूढ़ हो गए हैं। आडवाणी जी होम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ गए हैं। दंगा कौन करायेगा? जात के आधार पर अधिकारियों का चयन नहीं करिये, जो अच्छे अफसर हैं, सक्षम अफसर हैं उनकी पोस्टिंग करिये और क्राईम रोकने की कोशिश करिये। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रमुखी देवी - उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक इनफौर्मेशन देना चाहती हूं कि जब माननीय मंत्री महोदय अपना उत्तर देंगें तो इसका भी उत्तर देंगें कि खगड़िया जिला में पिछले 4 प्रमण्डलों के आई०जी० और डी०आई०जी० स्तर के पदाधिकारियों की बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया बढ़ते हुए अपराध रोकने के संबंध में और उसके प्रति चिन्ता व्यक्त की गयी। वहाँ के सांसद और विधायकों की सुरक्षा पर चिन्ता व्यक्त की गयी और ऐसे समय में मेरा जो सुरक्षा कर्मी भेजा गया उसने कहा मैंने आज तक फायर नहीं किया, मैंने उसको लौटा दिया, इसका भी उत्तर सरकार देगी।

श्री सत्य नारायण सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की मांग पर जो कटौती प्रस्ताव पेश किया गया है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज जो विषय है गृह वह बहुत ही संवेदनशील विषय है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वहाँ की जनता की जान माल की सुरक्षा। बिहार की जो कानून व्यवस्था है, आंकड़े में अलग बात है लेकिन मैं तो कहूँगा कि यहाँ जो 324-325 माननीय सदस्य बैठे हुए हैं अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलें कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है क्या? लौ ऐण्ड और्डर कौलेप्स कर गया है। ये आंकड़े भी बतलाते हैं और सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है और इस संबंध में मैं एक गृह मंत्रालय के अति गोपनीय रिपोर्ट को पढ़कर सुनाता हूँ और उस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय के लिए घोर चिन्ता का विषय बनी हुई है-खास तौर से उग्रवादी गुटों

तथा जमींदारों के समर्थक निजी सेनाओं के बीच जो अनवरत युद्ध चल रहा है वह नींद हराम कर देने वाला है। उग्रवाद तथा निजी सेनाएँ सतत रूप से अपना वर्चस्व कायम करने के लिए बिना किसी डर भय के निर्वाध रूप से युद्ध रत हैं। यह आम धारणा है कि राज्य प्रशासन यह सब एक नपुंसक दर्शक की तरह देख रहे हैं क्योंकि पिछले करीब 3 दशकों में राज्य नीति तथा प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण राज्य प्रशासन पंगू हो गया है। यह गृह मंत्री जी एक समझ है। केन्द्र के गृह सचिन ने सुझाव दिया है कि अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे को व्यवस्थित करने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि बहुत तरह की बातें चल रही है। हमारी पार्टी बिहार में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ है। 356 धारा के दुरूपयोग के विरोध में है लेकिन जो बिहार के हालात हैं हमारे मृगेन्द्र बाबू भाजपा के माननीय सदस्य ने रिपोर्ट दी है इसमें विस्तार से जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 1998 के सिर्फ शुरू के 5 महीने का फीगर लीजिये। बिहार में कूल हत्या और अपराधकर्म पिछले 5 महीने में हुए हैं।

उपाध्यक्ष - वह तो मृगेन्द्र बाबू पढ़ दिए हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, मैं विस्तृत आंकड़ा नहीं देकर सिर्फ यह आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं कि विगत पांच महीनों में बिहार में कुल अपराधों की संख्या ५३४०५ है जिसमें हत्याओं की संख्या ९९५ हैं अपहरण की घटना बिहार में जो हुई उसकी संख्या ११९१ है।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में १९९६-१९९७ में अपराधों की संख्या ८५०० जिसमें ५१८५ हत्यायें हुई। इस प्रकार तुलनात्मक जब हम देखते हैं तो काफी का अंतर है। उपाध्यक्ष महोदय, विगत साल का ही देख लिया जाय सिर्फ घटना जिला में इसी जून महीने में ३२ हत्यायें हुई हैं। इतना ही नहीं एक दर्जन डकैती हुयी जिसमें नकदी २३ लाख लूटा गया। डेढ़ दर्जन वाहनों का लूट हुआ जिसमें ११ लाख

की संपत्ति लूटी गयी। महोदय, सबसे बात शिवहर के एस०पी० को पटना शहर में लूटा गया। पूर्व आई०जी० (जी० नारायण) के दूकान में डकैती हुयी। महोदय, पिछले तीन वर्षों में ४ एम०एल०ए० मारे गये। दो एम० एल०ए० तो गत महीने मारे गये। इस प्रकार महोदय आज जो हालात हैं जेल से कोर्ट जाने के रास्ते में दो कैदी मारे जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज बिहार में कानून व्यवस्था की ऐसी हालात क्यों हैं ? इसका क्या कारण है? क्रिमिनलाइजेशन औफ पौलटिक्स और पौलटिकलाइजेशन औफ क्रिमिनल्स हो गया है। यह ठीक है कि १९४७ में पोलिटिकल मर्डर बिहार में हुआ या अब्दुलबारी की सबसे पहले हत्या हुयी थी। लेकिन पिछले आठ वर्षों में यह चरमसीमा पर पहुंच गया है। इसके पीछे कारण है जिसको देखना पड़ेगा। एक तो हम राजनीतिक पोलिटिकल पैट्रोनेज देते हैं अपराधियों को। हमारे बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोलिटिकलाइजेशन हो गया है। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप डेमोरलाइज होकर बैठ गया है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे यहां इन अपराधों का बढ़ना। अपराध बढ़ने का और भी कुछ कारण है जिसके कारण उग्रवाद बढ़ रहा है। वह है लैंड रिफार्म। जबतक भूमि सुधार कानून को सही अमला जामा नहीं पहनाया जायेगा उग्रवाद बिहार में बढ़ेगा इसको कोई रोक नहीं सकता। और यह भी एक कारण है हमारे बिहार के अन्दर, जिसके चलते अपराध बढ़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं कुछ सवालों को रखना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष – दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सत्यनारायण सिंह – महोदय, यह जो बिहार की हालत है, उसके लिये वर्तमान शासक भी कम दोषी नहीं हैं। इसका मुख्य कारण है कि आज जो अच्छे आफिसर हैं, जो अच्छे-अच्छे हैं उनको सचिवालय में शंटिंग पोस्ट पर

रखा जाता है और वे दिल्ली चले जाते हैं और जो भ्रष्ट और निकम्मे हैं उसको जिला में एस०पी० बना कर अथवा थाना में दारोगा, थाना प्रभारी बना कर रखते हैं। हमारे जिले में एक के० के० वर्मा एस० पी० थे। ट्रांसफर अब हुआ ज़ाकर। उन्होंने आने के समय 25 लाख रुपये कलेक्ट किया। आते समय मर्डर, बैंक रौबरी, किडनैपिंग के केसेज को 50-50 हज़ार रुपये लेकर फाईनल कर दिया। एक रामचन्द्र राय थे एस०पी०, वे तुतली सिंह गिरोह से मिले हुए थे और प्रति माह उनको एक लाख रुपया उस गिरोह से बंधा हुआ था। ऐसे बहुत एस०पी० हैं बिहार में जो जिलों में हैं और अच्छे आफिसर सचिवालय में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पॉलिटिकनाईजेशन ऑफ क्रिमिनलाईजेशन और क्रिमिनलाईजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर तो यहां बहुत कहां जा सकता है। केवल शासक पार्टी के ही लोग नहीं हैं इसमें, मैंने पहले भी कहा, छाती पर हाथ रख कर बोलिये, कोई किसी से कम नहीं है। गत लोक सभा का जो चुनाव हुआ जिसको आजन्म कारावास का दंड मिला है, वैसे रणवीर यादव जी 5 वर्ष तक विधायक भी रहे यहां, मुझे दुख और अफसोस होता है, कुछ दिन पहले मई महीने में नाव दुर्घटना हमारे यहां हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री लालू प्रसादजी और वर्तमान मुख्यमंत्री भी गयी थीं, रणवीर यादवजी ने जो हाल किया, वे जानते हैं। वे अपराधकर्मी हैं, उसके फादर पुलिस के काउंटर में मारे गये थे। वे आजन्म कारावासी थे। यही सदन है, पांच वर्ष रहे इसी सदन में निर्वाध गति से पूरे बिहार में घूमते रहे, छः माह भी कभी जेल में नहीं रहे, बल्कि शासक पार्टी के बरदहस्त के चलते वे आबाद रहे। चाहे आज आप उनका सामान फिंकवा दीजिये। दो-दो क्वार्टर रखे रहे, इतना उनको राजनीतिक संरक्षण दिया गया है। पहले हम और ऐसे लोगों को संरक्षण दें और जब विरोध में जाता है तो क्रिमिनल हो जाता है। आज दुख हो रहा है, जनता दल के लोग शरदजी और रामविलासजी जैसे लोग रोज जाते हैं उनके घर पर। चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, अगर अपराधियों

को राजनीतिक संरक्षण देंगे तो क्या होगा?

श्री जयप्रकाश नारायण यादव - उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, जिस घटना के बारे में, रणवीर यादवजी मंच जा आने के लिये लगातार प्रयास करते रहे, आदरणीय लालूजी और राबड़ी देवीजी ने साफ-साफ इन्कार किया कि ऐसे लोगों को किसी कीमत पर मंच पर चढ़ने नहीं देंगे और यही हुआ।

श्री सत्यनारायण सिंह - इसके लिये धन्यवाद जब 90 से 95 तक एम०एल०ए० थे तो कितनी छूट आपने ही दी, इनसाईड और आऊटसाईड विधान सभा के टूर का पैसा भी उनका निकला।

श्री मुंशीलाल राय - जैसे सत्य नारायण बाबू एम०एल०ए० को छूट मिला है, वैसे ही कोई एम०एल०ए० रहेगा तो छूट मिलती है।

श्री सत्यनारायण सिंह - महोदय, जेल में रहने पर नहीं मिलेगा मंत्रीजी। महोदय, कानून व्यवस्था की जो हालत बिहार में है, प्रभात खबर में देखिये - समस्तीपुर में 11 व्यवसायी इस साल में मारे गये और 8 साल में 90 हत्याएं हुई। सारे व्यवसायी वहां से पलायन कर गये। वही हाल मोकामा और बड़हिया का है। धधें नहीं लग रहे हैं, उसका क्या कारण है? कानून व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति। उद्योग धंधे आज ठप हैं।

महोदय, लालूजी जब 95 में दुबारा जीते थे तो बहुत देशों का भ्रमण किया था इन्होंने और कहा कि औद्योगिक क्रांति कर देंगे, जाल बिछा देंगे। बिहार का ढाई तीन करोड़ रुपया इस स्टेट के खजाने का पैसा खर्च हुआ, उसका क्या हुआ ?

(व्यवधान)

महोदय, राजनीतिक हस्तक्षेप का यह हाल है आज के टाईम्स ऑफ इंडिया में निकला है- ''निनिस्टर विजिट्स मर्डरर, जेल स्टाफ आस्क्ड टु टेक केयर।''

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का उल्लेख टाइम्स ऑफ इंडिया के 6 जुलाई के पेपर में है। महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री मृगेन्द्र प्रताप जी ने बताया, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, आज कैसे हमारा पुलिस पदाधिकारी काम करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले मई महीने में हमारे विधान-सभा क्षेत्र में 4 आदमी मर्डर हुआ था, वे सी०पी०एम० समर्थक थे, एक ही जाति विशेष के लोग थें हमारे क्षेत्र के एम०पी० ने चौथम ब्लॉक के बी०डी०ओ० के सामने चौथम थाना के दारोगा को बुलाकर डॉटा और कहा कि तुमने वहाँ पर क्यों कुर्की जप्ती किया, महोदय, जब इसतरह की बात एक राजनीतिक दल द्वारा की जायेगी तो कैसे कानून व्यवस्था में सुधार होगा। हमारा दल या कोई भी राजनीतिक दल अगर किसी अपराधकर्मी को संरक्षण देगा तो क्या उससे विधि व्यवस्था में सुधार होगा?

उपाध्यक्ष - अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार पुष्पम।

श्री सत्य नारायण सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट का और समय दिया जाय। महोदय, अभी माननीय सदस्या श्रीमती चन्द्रमुखी देवी जी ने ठीक ही कहा कि खगड़िया में 9 जिलों में वरीय पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, उसमें सबसे ज्यादा अपराधकर्मी को चिहिन्हत किया गया, नौगछिया जिला को। उपाध्यक्ष महोदय, नौगछिया का तुतली सिंह और धीरज यादव गिरोह का आतंक रहता है, खासकर बेलदौर जो हमारे विधान-सभा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर इन गिरोहों द्वारा आतंक मचाया जाता है। महोदय, एक बात में बता देना चाहता हूँ कि एक राजनीतिक दल के नेता का संरक्षण उसको प्राप्त है। महोदय, तो कैसे पुलिस कानून व्यवस्था में सुधार करेगी।

उपाध्यक्ष - अब आप समाप्त करें।

श्री सत्य नारायण सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, रास बिहारी मंडल है, जिनका आतंक नौगछिया से लेकर पिरपौंती तक का वह सरगना है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि रास बिहारी मंडल एवं दीना यादव जिनका

आतंक नौगछिया से लेकर पीरपैती तक का इलाका है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाय, अपराधकर्मियों को विधान-सभा और पार्लियामेंट का जो टिकट देते हैं, उसपर अविलंब रोक लगायी जाय, इतना ही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

उपाध्यक्ष - जो संसद-सदस्य हैं, उनकी अनुपस्थिति में इस सदन में कोई चर्चा नहीं होगी। संसद-सदस्य के संबंध में जो कुछ कहा गया है उसको कार्यवाही से हटा दिया जाये।

श्री सुनिल कुमार पुष्पम - उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा गृह विभाग की जो मांग पेश की गई है उस के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, आज सूबे बिहार की जो स्थिति है, उस को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रशासन को आधुनिकतम हथियार की जरूरत है। बिहार में ऐसे अनेक थाने हैं जहां गाड़ियां उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप अगर कहीं कोई क्राईम होती है, कहीं डकैती होती है और थाना को जब खबर होता है तो थाने के पास गाड़ी नहीं रहने के कारण वह तत्काल घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाते हैं।

महोदय, मैं आप के माध्यम से सरकार का ध्यान समस्तीपुर जिला की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज समस्तीपुर जिला की जो स्थिति है वह पिछले कई सालों की अपेक्षा इस साल बहुत अच्छी स्थिति हैं। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज समस्तीपुर जिला का प्रशासन का जो महौल है, वहां के जो आरक्षी अधीक्षक हैं सब ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। सब ठीक-ठाक चल रहा है। जहां तक मेरे विधान-सभा क्षेत्र हसनपुर का सवाल है, वह चार-पांच जिलों-दरभंगा, बेगुसराय, सहरसा और समस्तीपुर का बोर्डर एरिया पड़ता है। इस प्रकार हसनपुर चार जिलों का बोर्डर एरिया पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि हसनपुर चार जिलों का बोर्डर एरिया होने के कारण दरभंगा, बेगुसराय, सहरसा का वह क्राईम का

अड्डा बना हुआ है। वहां बहुत सारे गिरोह जैसे सहनी गिरोह, यादव गिरोह आदि तीन चार गिरोह सक्रिय है। वे सब दिन-दहाड़े खास कर हसनपुर में, महोदय, परसों की घटना है, मेरे विधान के उज़ान गांव में एक साहू को उनके द्वारा रंगदारी टैक्स नहीं देने के कारण दिन-दहाड़े बहुत बुरी तरह से मारा-पीटा गया और वहां के स्थानीय लोग उक्त गिरोह के डर से थाना नहीं जा सके और प्राथमिकी भी दर्ज नहीं करा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः समस्तीपुर के आरक्षी अधीक्षक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां का पुलिस प्रशासन मामले को खुद देखते हैं कि प्रशासन का कार्य अच्छी तरह से किस प्रकार चले। साथ ही जो पुलिस पदाधिकारी अच्छे कार्य करते हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। हसनपुर थाना के थाना प्रभारी बहुत अच्छा काम करते हैं मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मेरे विधान-सभा क्षेत्र में विधान है जहां मैं चाहता हूं कि एक अच्छे पुलिस अफसर की पदस्थापन हो और वहां के क्राईम की स्थिति में सुधार लाया जा सके। महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि अच्छे अफसर को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। विभुतिपुर के थाना प्रभारी अच्छा काम करते है। अपराधकर्मियों को मार कर भगा देते थे। वहां एक अच्छी स्थिति बन गयी थी, एक अच्छा महौल कायम हो गया था। लेकिन कुछ दबाव के कारण उनका स्थानान्तरण हो गया है जिससे वहां के राजनीतिक कार्यकत्ताओं को बहुत गुस्सा है। एक अच्छे अफसर को मान-सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनका पदस्थापन विभतिपुर थाने में ही रहने दिया जाये।

महोदय, हसनपुर थाना और विधान थाना में गाड़ी नहीं है जिसके कारण वहां के पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर तत्काल पहुंच नहीं पाते है इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त दोनों थानों में अविलंब गाड़ियों की व्यवस्था कराई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हसनपुर और विथान थाने को अपना भवन नहीं है, वह दोनों किराये के मकान में है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त दोनों थानों का भवन शीघ्र बनना चाहिए ताकि वहां सही ढंग से काम कर सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हेम लाल मूरमू - उपाध्यक्ष महोदय, आज तो सरकार द्वारा मांग प्रस्तुत किया गया है मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, अपराध का जा डाटा है उस के मकड़जाल में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपके माध्यम से सरकार को दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार ने जो मांग पेशकिया है, निश्चित रूप से यह मांग मंजूर होना चाहिए। आज पूरे बिहार में जो पुलिस विभाग की संरचना है इस में सभी थानों में अच्छी-अच्छी गाड़ियां उपलब्ध होनी चाहिए और सभी पुलिस बल के पास अत्यंत आधुनिक हथियार रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज उग्रवादी, अपराधी आधुनिकतम हथियारों से लैश हैं। हमारे पुलिस बल के पास भी ऐसे ही हथियार उनसे मुकाबला करने के लिए होना चाहिए ताकि आज ये जो अपराधी तत्व आधुनिकतम हथियार का इस्तेमाल करने वाले उग्रवादी हैं, क्रिमिनल हैं, इनके साथ ये मुकाबला कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज विधि-व्यवस्था का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। हमारी बिहार पुलिस कैसे विधि-व्यवस्था को ठीक करेगी, इसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति होने की आवश्यकता है और जिस ढंग से पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार का आलम है, बिहार की जनता पुलिस के नाम से घृणा करती है। इसको कैसे दूर किया जाए। इस पर तमाम सरकार ने लोगों को, आला अफसरों को गंभीरता से सोचना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जो पुलिस प्रशासन है, उसका जो सबसे नीचे का

हिस्सा है जिसको आज गांवों में रहना चाहिए, उनको ग्रामीण पुलिस कहा जाता है, उनको चौकीदार कहा जाता है। आज इन चौकीदारों की क्या स्थिति है। वह थाने के दारोगा के घर में बच्चों को खिलाता है, कोई कपड़ा साफ करता है तो कोई पानी ढोता है और इससे जो समय बच जाता है तो वह चौकीदार दारोगा के लिए तहसीलदार का काम करता है। गांवों में जा कर दारोगा के लिए मुर्गा, खस्सी और पैसा तहसील करके लाता है। बड़ी कठिन बात है। इनकी स्थिति ऐसी दयनीय बना दी गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे झारखण्ड क्षेत्र में पुलिस विभाग के पदाधिकारियों और दारोगा का पदस्थापन होता है उसमें निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की सरकार कहलाने वाली, गरीब लोगों की सरकार होने का दावा करने वाली सरकार को इस बात को गंभीरता से सोचना होगा कि उस क्षेत्र में, आप वहां जिस क्षेत्र में जाइएगा तो पाइएगा कि एक तरफ से शर्मा जी, दूबे जी, चौबे जी ऐसे तमाम लोग उस क्षेत्र में मिलेंगे। दूसरे लोग नहीं मिलेंगे। इस तरह से उस क्षेत्र में ऐसे पदाधिकारी लोगों को, जो उस क्षेत्र के हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के हैं उनको पदस्थापित करना चाहिए। आज इन लोगों को उत्तर बिहार और मध्य बिहार में पदस्थापित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस व्यवस्था को दुरूस्त नहीं किया जाएगा तब तक बहुत मुश्किल होगा विधि-व्यवस्था को ठीक करना। महोदय, हमारे सामने आज सबसे बड़ी समस्या है होमगार्ड की समस्या का समाधान करने की। हम लोगा देख रहे हैं कि आज पूरे बिहार में इन पर निर्भर रहना पड़ रहा है प्रशासन को। ये लोग सबसे गरीब, समाज के सबसे गरीब परिवारों से आते हैं। होम-गार्ड के जवानों ने पिछले चुनाव का कार्य कराया लेकिन आज तक होम-गार्ड की बहाली नहीं हो रही है। ये लोग गांधी सेना है, इनको न पैंट है, न कूर्त्ता है, न लाठी है। किसी चीज का ठिकाना नहीं है। लेकिन ये बेचारे सेवा करते चले आ रहे हैं। ये गांधी जी द्वारा

दिखाये गए अहिंसा के रास्ते पर चल कर सरकार और आम लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं। सरकार को इस ओर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज थाने की क्या स्थिति है। पहले कहा जाता था कि एस० पी० दारोगा का भगवान होता है लेकिन आज दारोगा की एस०पी० का भगवान है क्योंकि वही उसका अन्नदाता है। इसलिए आज बहुत ही कठिन स्थिति हो गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि हमारे लोग, आदिवासी समाज से आने वाले अच्छे पदाधिकारी हैं, आला आफिसर हैं। इनमें से एक हैं श्री रामेश्वर उरांव जी, जो बिहार सरकार के आदेश से बहुत सारे सराहनीय कार्य कर चुके हैं। इन्होंने पिछले दिनों आडवाणी जी जैसे आदमी को सरकार के आदेश से, साम्प्रदायिक दंगा रोकने के लिए, उनकी गिरफ्तारी किया था।

महोदय, आज बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे अफसरों को आज कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। आज के ढ़ाई-तीन साल से सी०आई०डी० में काम कर रहे हैं। महोदय, हमारी समझ में सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। महोदय, आज जो ये तमाम स्थिति बिहार के अन्दर पैदा हो रही हैं, चाहे वह सामाजिक दंगा की स्थिति हो, आज हम पुलिस के प्रति जो आस्था रखते हैं, सबसे पहले सरकार को एक बात करनी चाहिए कि सभी थाना परिसद में जो बजरंगबली का मन्दिर बनाया गया है, इसको ध्वस्त करा देना चाहिए। क्योंकि इससे पुलिस बल के अन्दर एक साम्प्रदायिक भावना पैदा होती है और इस भावना के चलते पुलिस में साम्प्रदायिकता बढ़ती चली जा रही है।

(व्यवधान)

महोदय, इस तरह से ये लोग हमारा समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री जगदीश शर्मा - उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था

का प्रश्न यह है, महोदय, मैं बहुत कम सदन में बोलता हूं और डिस्टर्बेंस नहीं करता हूँ, आज मैं 5 टर्म से यहाँ एम०एल०ए० हूँ लेकिन महोदय, यह सदन विभिन्न मर्यादाओं और परम्पराओं से चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि जातीय उन्माद भड़के, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि धार्मिक उन्माद भड़के। महोदय, ये सभी तो बातें हो रहीं हैं, इसको यहाँ से एक्सपंज करवाइये।

श्री कमल पासवान - उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, हम सारे धर्मों का आदर करते हैं, उसकी ईज्जत करते हैं। माननीय सदस्य ने जिस प्वायंट को उठाया है, यह सही बात है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उन सारे कार्यालय...

उपाध्यक्ष - श्री कमल पासवान जी, आप मंत्री हैं, आप अपने किसी दूसरे माननीय सदस्य को इस बात को कहने के लिये बोलिये। आप मंत्री हैं, आप बैठ जाइये।

श्री कमल पासवान - महोदय, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए। हम सारे धर्मों की ईज्जत करते हैं,लेकिन सरकारी जमीन में सिर्फ हनुमान जी का मन्दिर ही क्यों हो, क्यों नहीं उसमें मस्जिद बनता है, क्यों नहीं उसमें गिरिजाघर बनाया जाता है ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर यह काम हो रहा है तो यह अच्छा नहीं है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष - माननीय श्री कमल पासवान जी, आप मंत्री हैं इसलिए हमने कहा था कि किसी दूसरे माननीय सदस्य से कहलवाइये।

श्री हेम लाल मुरमू - महोदय, मैं कह रहा था कि सरकार की एक परिपाटी है कि पदाधिकारियों की सेवा-अवधि में विस्तार दिया जाता है। मैं इस संबंध में सरकार से कहना चाहूँगा कि अवधि विस्तार की जो नीति है, यह ठीक

नहीं है और पिछले दिनों देखा गया कि बिहार के आला अफसरों के सेवा-अवधि विस्तार के दरम्यान बहुत सारे बहारियाँ और काफी उलट-फेर के मामले हुये हैं। इसलिए इस बात पर माननीय मंत्री जी को गम्भीरतापूर्वक विचार करके बयान देना चाहिए।

महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि दिनांक 21.2.98 को गुमला जिला के कुडेक थाना में प्रदीप कुमार नाम का जो दारोगा ने अलबनबाड़ा एक आदिवासी को पुलिस लौक-अप में मारते-मारते हत्या कर दिया।

महोदय, आज तक उस सवाल पर क्या हुआ, उसका जवाब देंगे मंत्री जी। लेकिन इस मामले के बारे में मानवाधिकार आयोग को भी लिखा गया है, इसलिए ऐसे पदाधिकारियों को उस क्षेत्र से हटाया जाय और निश्चित रूप से जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले पदाधिकारी हैं, उनका वहां पर पदस्थापन किया जाय, तभी उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार रूकवा सकता है और आम जनता के लोगों में विश्वास जग सकता है। महोदय, जो व्यवस्था है पुलिस की, जो सामाजिक उत्पीड़न का मामला है, उसमें पुलिस का क्या रौल है, पुलिस का क्या दृष्टिकोण है। इस तरह के मामले में पुलिस लोग बड़े और बलिष्ठ लोगों के पक्ष में चले जाते हैं, जिसके चलते हरिजनों को, आदिवासियों को जो न्याय मिलनी चाहिए, वह न्याय नहीं मिल पाती है। वह न्याय बड़े और सबल लोगों के पक्ष में चली जाती है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, विधि-व्यवस्था की बात है, सिर्फ बिहार सरकार विधि-व्यवस्था के लिए दोषी नहीं है। अभी जो केन्द्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वे बिहार में आर.एस.एस. कैडर का पर्दापण करा रहे हैं और इसके चलते विधि-व्यवस्था खराब हो रही है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव नारायण आर्य - उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री हेमलाल

मुरमू जी जिन बातों का उल्लेखय किया है, वह आपत्तिजनक बात है, इसको प्रोसिडिंग से निकाला जाय। महोदय, किसी धर्म पर प्रहार नहीं करना चाहिए। हिन्दुस्तान में एक समाज में सभी धर्म के लोग रहते हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष - माननीय सदस्य ने सजेशन दिया, हमने सुन लिया। आप बैठिये। माननीय सदस्य श्री मुन्द्रिका सिंह यादव, आप अपना भाषण शुरू करें।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव - उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पर बहस चल रही है। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण और बिहार की स्थिति के बारे में बहुत ही ठोस सुझाव देने का काम किया है। हमारे पूर्व विद्वान वक्ताओं ने, माननीय सदस्यों ने गृह विभाग पर बहस में भाग लेते हुए बहुत सारे लम्बे-चौड़े आंकड़े प्रस्तुत किये हैं।

(व्यवधान)

महोदय, पूर्व के विद्वान वक्ताओं ने सूबे बिहार के जो सबसे बड़ी पंचायत विधान-सभा में जो बहस चलायी जा रही है, उसमें जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, वे आंकड़े बता रह हैं। सरकार का जो बजट है, उसकी जो मांग है, वह प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ उनके आंकड़े बता रहे हैं, जो अपराधिक घटनायें हैं, उसमें दिन-प्रतिदिन दिन-दूनी और रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। महोदय, इस अहम सवाल पर सदन में मिश्चित रूप से निष्पक्ष रूप से बात होनी चाहिए। चूंकि सदन में सूबे बिहार है 9 करोड़ महान जनता के हक-हकूक और जान-माल की हिफाजत की बात है। जब विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष के लोग कोई उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे थे तो कोई मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे थे, कोई आडवाणी जी के बारे में चर्चा कर रहे थे।

महोदय, यह सदन पूरे बिहार की महान जनता की समस्या के लिए,

उसके समाधान के लिए, जिन माननीय सदस्यों को वहां से चुनकर यहां भेजने का काम किया है, इतने संवेदनशील विषय पर सारे लोगों को जात-पात धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। महोदय, आप आपराधिक घटनाएं जो आये दिन हो रही है, नरसंहार हो रहा है, हत्या हो रही है, लूट हो रही है, डकैती, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं जो हो रही है यह कोई नई घटना नहीं है। इस ऐतिहासिक बिहार की धरती पर बड़े-बड़े नरसंहार हुए हैं, दलेलचक बघौरा में नरसंहार हुआ, जमुआ में नरसंहार हुआ, अमीनाबाद में नरसंहार हुआ कंसारा में नरसंहार हुआ। हाल के दिनों में भी सुबे बिहार में और मध्य बिहार में भी हत्याओं का सिलसिला जारी है। महोदय, अभी हाल के दिनों में बिहार के जहानाबाद की धरती पूरे देश के लिए उदाहरण बना जहां के लक्ष्मणपुर बाथे के नरसंहार में 61 गरीबों की निर्मम हत्या हो गयी। महोदय, इतना बड़ा जहां नरसंहार हो रहा है आज उस संवेदनशील विषय को कितने हल्के ढंग से चलाया जा रहा है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हो। महोदय, यदि सही मायने में इसके निवारण की बात करना चाहते हैं, सही मायने में यदि आप हत्या पर रोक लगाना चाहते हैं, डकैती पर रोक लगाना चाहते हैं, अपहरण पर रोक लगाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जिला में जो हो रहा है, जिला को बेचा जा रहा है, थाना को बेचा जा रहा है, ब्लौक को बेचा जा रहा है, अंचल को बेचा जा रहा है, निश्चित रूप से इस पर रोक लगाना होगा। जब यहां से जिला को बेचा जाता है तो जिला में एस०पी० जाकर सारे थाने को एक-एक कर के बेचने का काम करते हैं। इसलिए महोदय, हम कहना चाहते हैं कि जा सरकार की नजर में निष्ठावान पदाधिकारी हैं, जो अच्छे आई०ए०एस० पदाधिकारी हैं, उनको आप निश्चित रूप से जिला में भेजने का काम करें। अगर निष्पक्ष, निष्ठावान, ईमानदार एस०पी० जिला में जायेगा तो वह थाना को बेचने का काम नहीं करेगा और ईमानदारी पूर्वक जिला में शासन चलाने का काम करेगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव - उपाध्यक्ष महोदय, हम व्यवस्था पर हैं। माननीय सदस्य श्री मुन्द्रिका बाबू बहुत ही पुराने सदस्य हो गये हैं जिस तरह से वे अपनी बात को रखे, कि बेचा जाता है यह बहुत ही आपत्तिजनक है। कर्त्तव्यनिष्ठ अफसर को ही ज़िला में पोस्टिंग किया जाता है। अतः बेचे जाने वाली बात को प्रोसिडिंग से निकलवा दिया जाय।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव - महोदय, आज राज्य में राजनीतिक हत्याएं हो रही है। राजनीतिक हत्याएं भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में होती रही है। अभी श्री अब्दुल वारी जैसे मजदूर नेता की हत्या हुई। श्री अब्दुल वारी जहानाबाद की भूमि से पैदा होकर मजदूर नेता के रूप में उभरे। इसी धरती पर दलितों, शौषितों के नेता स्व० जगदेव बाबू को 5 सितम्बर, 1994 को कुर्था की धरती पर जनसभा को नेतृत्व करते समय कांग्रेस के शासनकाल में पुलिस की गोली से उनकी निर्मम हत्या की गयी थी। उनकी हत्या की जांच के लिए जांच कमीशन भी बनाया गया था लेकिन उन दिनों की सरकार ने रफा-दफा कर दिया था महोदय, और मंत्री सदन में महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब यहां मुख्य मंत्री के रूप में थे, सदन में उन्होंने घोषणा किया था कि शोषितों, दलितों के मसीहा अमर शहीद जगदेव बाबू की जो हत्या की गई, मैं उसकी जांच कराने का काम करूंगा। सही माने में आप राजनीतिक हत्या की रोक लगाना चाहते हैं तो माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने जो इस सदन में घोषणा किया है कि हम जगदेव बाबू की हत्या की जांच पुनः कराने का काम करेंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जगदेव बाबू की हत्या सरकारी घोषणा के आलोक में पुनः जांच कराई जानी चाहिए। लगातार यह क्रम जारी है महोदय, आप सभी जानते हैं महोदय, युवा जनता दल नेता सरदार अभय सिंह की हत्या 7 मार्च, 1998 को जहानाबाद में दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई थी महोदय। आज तक हत्यारे पकड़े नहीं गए महोदय। सरकार ने विधान परिषद में घोषणा की थी कि हत्यारे पकड़े जायेंगे। उनकी राजनीतिक हत्या हुई है। उनके आश्रितों को, उनके परिवार के लोगों को

मुआवजा दिया जायगा, नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज तक नहीं हुआ महोदय। एक सप्ताह के अंदर ही रामानन्द यादव घोषी थाना हित्चौती गांव का जो मोटर साइकिल से जहानाबाद आ रहे थे, अपराधियों ने रास्ते में हमला किया परंतु वे बाल-बाल बच गए बुरी तरह घायल हुए, परन्तु उनके चाचा की निर्मम हत्या कर दी गई लेकिन आज तक अपराधी पकड़े नहीं गए, जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। एस.पी. कहते हैं डी.आई.जी. रोक लगा दिए, डी.आई.जी. कहते हैं कि हमने कोई रोक नहीं लगाया। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सरकारी प्रावधान है कि जो उग्रवादी हत्या में मारे जायेंगे, उनके परिवार को एक लाख रुपया दिया जाएगा और नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज इस दिशा में खुले आम यह कहना चाहते हैं कि जो गरीब उग्रवादी हत्या में मारे जा रहे हैं हरिजन मारे जा रहे हैं, दलित मारे जा रहे हैं उनको वर्षों-वर्ष तक सरकारी घोषणा के अनुसार, सरकारी परिपत्र के अनुसार मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष - अब आप समाप्त करें।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव - महोदय, हमारे पास करपी थाना में एक गांव है जहां राम सिंह यादव मुखिया का 14 अगस्त, 1997 को उग्रवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। महोदय, इस सदन में दावे के साथ यह कहना चाहता हूं कि सूबे बिहार में शायद कोई ऐसा ईमानदार मुखिया रहा होगा, तीस वर्षों तक मुखिया रहने के बाद आज भी कोई जा कर देख ले-रहने के लिए उस मुखिया को घर नहीं है, लेकिन जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ वह व्यक्ति आवाज उठांता था जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। आज तक मुआवजा नहीं दिया गया, नौकरी नहीं दी गई। उसी पलासी गांव में महोदय, एक सप्ताह बाद 10 लोगों की निमर्म हत्या कर दी गई, हरिजनों की हत्या कर दी गई, उसमें भूमिहार जाति के लोग थे, लेकिन आज तक उन्हें नहीं पकड़ा गया। मैं कहना चाहता हूं महोदय कि आज यह जो सिटी में व्यापारी के लड़के की हत्या हुई थी, यहां की पुलिस जा कर अवध यादव

को जहानाबाद से ला कर पकड़ कर चार दिन तक टॉर्चर करते रही, जब कि बाद में नाम आया अवध यादव कलइठा का रहने वाला है, उसने हत्या की। जब पुलिस वालों को इतना पता होगा, इतना कम्युनिकेशन गैप होगा, जहां इनका सी.आई.डी. है, स्पेशल ब्रान्च हैं, लेकिन निर्दोष लोगों को पकड़े जाते हैं और जो सही माने में अपराधी हैं, नरसंहार करने वाले हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है।

उपाध्यक्ष - अब आप समाप्त करें। आप सीनियर मेम्बर हैं।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव - महोदय, माननीय सदस्य नवल किशोर राज जी बैठे हुए हैं उनके अंगरक्षक ....

उपाध्यक्ष - अब आप समाप्त करें।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव - दो-दो बार उनपर हमला हुआ, लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य विनोद कुमार यादवेन्दु जी बैठे हुए हैं, इनके साथ बेला की पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, अपमानित उनके साथ आज कुछ नहीं किया गया है। और महोदय, कल की यदुवंश सिंह जो ....

उपाध्यक्ष - माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव - महोदय, हाजीपुर में हत्या हुई, हम उनके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। महोदय, गया जिला में एक नसीमचक गांव है जहां हरिजनों का गांव है, लगातार चार हरिजनों की हत्याएं हुई हैं और..

उपाध्यक्ष - आपका समय समाप्त हो गया। माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ सिंह।

श्री विश्वनाथ सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, हम बोलने के लिए खड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री मुन्द्रिका सिंह यादव - उपाध्यक्ष महोदय .....

उपाध्यक्ष - आपका समय समाप्त हो गया, आप आगे बोलियेगा तो वह फिर लिखा नहीं जायेगा, आप बैठिये।

श्री विश्वनाथ सिंह - उपाध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की मांग पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। महोदय, आज गृह विभाग में जो अत्याचार, बलात्कार और हत्याएं हो रही है, वह तमाम इस सामाजिक न्याय की सरकार में गरीबों, पिछड़ों दलितों की ही हत्याएं हो रही हैं। महोदय, आज जो स्थिति है कि वर्ष 1947 से लेकर यानी आजादी के बाद से 14 जून तक हमारे बिहार प्रान्त में पूर्व सांसद, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक कुल मिलाकर आज 23 विधायकों, सांसदों की हत्याएं हुई हैं, लेकिन यह सरकार, यह गृह विभाग आज तक इसको रोकने में इस पर रोक लगाने में असफल रहा है। महोदय लाखों, अरबों, करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी अपराध बन्द नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। महोदय नरसंहार वर्ष 90 से लेकर वर्ष 97 तक 120 हुए हैं, सैकड़ों आदमी नरसंहार में, भूमि विवाद को लेकर जातीय संघर्ष में, राजनीतिक संघर्ष को लेकर लोगों की हत्याएं हुई हैं। महोदय, आज स्थिति है कि लोग मारे जा रहे हैं और हत्यारे पकड़े नहीं जा रहे हैं। अभी महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अब्दुल बारी, मन्जूर हसन, सूरज नारायण सिंह, जगदेव प्रसाद, ललित नारायण मिश्र, सीताराम मिश्र, वी.पी. सिन्हा, रामदेव सिंह, राम नगीना सिंह, विरेन्द्र सिंह महोबिया, वीर बहादूर सिंह, विनोद सिंह, त्रिलोकी हरिजन, नगीना राम, सूरज नारायण शर्मा, ईश्वरी चौधरी, हेमन्त शाही, कामाख्या नारायण सिंह, अशोक सिंह, देवेन्द्र नाथ दुबे, वृज बिहारी प्रसाद, अजीत सरकार वगैरह लोगों की हत्याएं हुई हैं। महोदय, सरकार घोषणा करती है कि मरने वाले के परिवारों के लोगों को लाखों-करोड़ों रुपये देंगे, लेकिन महोदय, लाखों रुपये

देने से यह अपराध, यह हत्याएं रूक नहीं सकती हैं। अगर यही स्थिति रहेगी तो पूरे बिहार में हत्याओं पर हत्याएं होगी रहेंगी और एक दिन ऐसा भी आयेगा कि घर के लोग ही हत्या कर देंगे रुपयों के लालच में। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने से और नौकरी देने से हत्याएं रुकने वाली नहीं हैं। महोदय, मैं बताता हूँ कि हमारे जिले में, हम गोपालगंज जिले के मीरगंज कन्सटिट्यूएन्सी के फुलवरिया ब्लॉक से आते हैं, वहां एक-डेढ़ साल से रोज हत्याएं हो रही है। अभी 3 जुलाई को हत्या हुई राजद के प्रखण्ड अध्यक्ष की।

हमारे नवजवान राजद के नेता माननीय सांसद श्री साधू प्रसाद यादव ने जिस आदमी का नाम उजागर किया है, पूर्व विधायक मीरगंज का उसकी हत्या में हाथ है लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं पिछले साल 15 मई, 1997 को पूर्व विधायक अपने भाई और भतीजे को खड़ाकराकर 5.00 बजे शाम में दिन दहाड़े दर्जनों आदमी के बीच गोली मरवा दिया। उस केस का आज तक कुछ नहीं हुआ। सरकार ने सी.आई.डी. कंट्रोल कराकर, आज भी वह राजद में बना हुआ है, साधू जी बोलते हैं कि हम लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ है। कम से कम राजद का नेता राजद से वैसे लोगों का खिलाफत कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। यह साधू जी की बहादुरी की बात है, तारीफ करने वाली बात है। सरकार में वह आदमी अभी भी बना हुआ है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम बताना चाहेंगे कि फुलवरिया के दर्जनों गांव में दो सा से शादी नहीं हो रही है, तिलक नहीं चढ़ रहा है, बारात नहीं आ रही है। वहां एस.पी. भेजे जाते हैं और कहते हैं कि हम क्रिमिनल पकड़ने नहीं आये हैं, हम लाश ले जाने आये हैं। अभी भट्टी साहब वहां गये थे। उनके समय में दर्जनों मर्डर हुए है।

उपाध्यक्ष - अब आप समाप्त करें।

श्री विश्वनाथ सिंह - महोदय, हम आपको बताना चाहते हैं कि सिवान के

छात्र नेता की हत्या हुई। आज तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। हम बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं अजीत सरकार की हत्या के लिये सी.बी.आई. से जांच कराने के लिये सरकार घोषणा की है लेकिन कब यह जांच शुरू होगी, सरकार इसका जवाब दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामेश्वर प्रसाद – उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन मे आज गृह विभाग पर चर्चा चल रही है। गृह विभाग अपने कार्यों में किस तरह दक्ष है सरकार यह बतलाने का काम करेगी लेकिन गृह विभाग के कार्यो से बिहार की जनता को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या न्याय मिल पा रहा है इसके लिये बिहार की जनता गवाह है, यह आंकड़ा बता रहा है। कितने गांव के गरीबों का नरसंहार हो रहा है, दलितों का नरसंहार हो रहा है, हरिजन एक्ट का उल्लंघन करके एक समान तरीके से देखा जा रहा है। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि गांव में पुलिस जाती है। इनके बैज पर लिखा रहता है रक्षा, लेकिन जनता इनको एक गेहूमन सांप के रूप में देखती है। क्या कंसेप्ट है इनका। इनको एक गेहूमन सांप की तरह देखा जाता है और जब डकैत डकैती करते हैं और डकैती करके बगल के रास्ते से भागते हैं तो पुलिस दूसरे रास्ता से जाती है ताकि डकैत भाग जायें। यह बिहार की पुलिस की दशा हैं नरसंहार बड़े-बड़े हो गये। पुलिस ने जो अपना चार्जसीट दिया है उसमें किस तरह से नरसंहार से बचने का काम किया है। यह बाथे का नरसंहार गवाह है। गवाह है बथानी टोला में जहां एक-एक अभियुक्त जेल से बाहर हैं। ये किस तरह से नरसंहार के साथ मिले जुले हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कि जब तक इस पुलिस का गुंडे गिराहों, से यह जो निजी सेनायें रणवीर सेना बनी है, सनलाइट सेना बनी है, इसकी संलिप्तता की जांच नहीं होती है तब तक यहां की विधि-व्यवस्था में सुधार नहीं लाया जा सकता है। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो इसको संरक्षण प्रदान करते हैं। यह बिहार की हकीकत है। यहां के पुलिस बल और पुलिस

औफिसर लोग उनसे सांठगांठ रखते हैं, संबंध रखते हैं। हमारे साथी ने चर्चा किया कि यहां राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। बहुत सारे मित्र बोले हैं कि उत्तर प्रदेश में घटना ज्यादा हुई है, कुछ बोलते हैं कि बिहार में घटना ज्यादा है लेकिन हम कहना चाहते हैं कि चाहें बिहार की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता को वहां की पुलिस मरवाती है तो वह क्राईम कर रही है, चाहे बिहार की पुलिस बिहार की जनता को संरक्षण प्रदान नहीं करती है तो यह क्राईम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि आज जो पुलिस के अन्दर जो भावना आप देख रहे हैं, यूनियन के चुनाव में पुलिस गोली चलाती है, हर जगह जाति की भावना से देखती है, पुलिस की बनावट और कन्सेप्ट है, आप चाहे लाख हथियार दे दीजिए, गोली दे दीजिए, इससे क्राईम रूक जायेगा, नहीं रूकने वाला है। बहुत से नये थाने खुल रहे हैं, बहुत से ऑफिसर बहाल हो रहे हैं। लेकिन पुलिस का कन्सेप्ट और बनावट ऐसी है कि यह चिंतन का विषय है, विचार का विषय है, विचारनीय है कि कैसे बदला जाए इस कन्सेप्ट को। हम कहना चाहते हैं कि चन्द्रशेखर की हत्या हो गया, रिटायड एस०पी० पर फ़ायरिंग होती है और एस०पी० का ट्रान्सफर कर दिया जाता है। इस तरह से आप अपराधी को बचाने का काम करते हैं। जो राजनीतिक हत्या होती है उसका आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। बक्सर में जो एम०पी० के उम्मीदवार थे, उन्हें आज तक मुआवजा नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष - अब आप का समय समाप्त हो गया।

श्री गुरूदास चटर्जी - उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चीज यह है सबसे जरूरी चीज यह है कि पुलिस विभाग का जो ट्रेनिंग है, ज़िस तरह से ब्रिटिश टाईम में पुलिस को जो ट्रेनिंग थी, जो पुलिस की सजावट थी, वही आज भी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस विभाग की

मानसिकता को कैसे चेन्ज किया जाए और आज इसके मानसिकता को चेन्ज करना चाहिए। दूसरी बात यह कि आज गिरावट की बात बहुत की जाती है। इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं कि आज से १५-२० दिन पहले में मोटरसाईकिल से धनबाद आ रहा था, कुछ सिपाही लोग जी०टी० रोड पर ट्रक रोक कर पैसा वसूल रहे थे, मैंने उन लोगों से पूछा कि इतनी लंबी लाईन क्यों लगी हुई है। इतनी बात सुनकर वह सिपाही बोला हमलोग तो दस रुपया ट्रक से लेते हैं, जहां पर मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री करोड़ों रुपया चोरी करते हैं, वहां पर आपकी नजर नहीं है। यह बात पिंचिंग करने वाली हैं, एक सिपाही के अन्दर यह बात आ रही है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले चीज यह है कि ऊपर से नीचे तक ठीक करने की जरूरत है, जब हम लोग ठीक होंगे तभी बोल सकते हैं। जब पुलिस के बजट को दिया जाए तो एक-एक पुलिस थाना का क्षेत्र २५ कि० मी० है और जब कोई केस होता है तो हम लोग कहते हैं कि वहां आकर केस देखिये, वह अपने मोटर साईकिल से जाकर वहां देखता है, थाना में एक पैसे का भी कन्टीजेन्सी नहीं है, वह दस रुपया भी खर्च नहीं कर सकता है। थाना में बराबर एस०पी० जाते हैं, डी०जी० जाते हैं लेकिन उसके पास कन्टीजेन्सी के लिए एक पैसा भी नहीं है। जब उसे गाड़ी की जरूरत होती है तो रोड पर जाकर गाड़ी पकड़ता है और पेसेन्जर को उतार देता है, पैसेन्जर गाड़ी के बाहर खड़े होते हैं।

बार-बार आधुनिक हथियार की बात की जाती है। हमने एक उग्रवादी से पूछा कि तुम्हारे पास हथियार कहां से आता है, तो उसने कहा कि हमारा सबसे बड़ा हथियार का साधन सरकार है। सरकार जितना आधुनिक हथियार पुलिस को देगी, हम लोग छीन लेंगे। इसलिए आधुनिक हथियार पुलिस को देने के पहले उसे ट्रेनिंग देना होगा, वह अपने हथियार को कैसे बचा सके। इसलिए सबसे जरूरी चीज है। पुलिस को ट्रेनिंग देने की। जब दारोगा २० कि० मी० अपनी गाड़ी से अपने पेट्रोल से जायेगा तो जिसका केस होता है उसी से पेट्रोल लेता है।

अब मैं कोयला क्षेत्र की बात करता है। मैं कहना चाहता हूं कि जिला में एस०पी० जो होता है, उसी पर यह छोड़ देना चाहिए कि वह दोष दारोगा की पोस्टिंग करे। आज मुख्य मंत्री हाऊस से, मंत्री हाऊस से और एम० एल० ए० का टेलीफोन जाता है कि फलां आदमी को फलां थाना में पोस्टिंग कीजिए। धनबाद का एस०पी० बहुत ईमानदार है, उसने कोयला माफिया और बालू माफिया को ठीक करने का काम किया है। मगर उस एस०पी० को हटाने के लिए कोयला माफिया और बालू माफिया, पटना में बैठकर पैरवी कर रहा है।

हम जानते हैं ये ईमानदार एस०पी० शायद ही धनबाद में रह रह पायेंगे, इसलिये हम चाहेंगे कि आप पुलिस बजट को ठीक करें, पहले आप अपने ठीक हो जायं तब सारा थाना ठीक हो जायेगा-मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष - माननीय सदस्य श्री यमुना यादव, आप अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करेंगे। इसके बाद सरकार का जवाब होगा।

श्री यमुना यादव - उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बजट के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सरकार की मांग है, उसमें कुछ सलाह देना चाहता हूँ। केवल पुलिस को गाली देने से काम नहीं चलेगा, यह बात सही है कि अभी जो लॉ एण्ड आर्डर का प्रोब्लम है, वह केवल बिहार में ही नहीं है, आप देखेंगे, हमारे साथी अखबार पढ़ रहे थे, नागालैण्ड की जो स्थिति है, आसाम की जो स्थिति है, त्रिपुरा की जो हालत है, कश्मीर की जो हालत है, आंध्रप्रदेश में पिपुल्स वार ग्रुप जो हैं, वहां की जो स्थिति है, वहां की स्थिति से बिहार की स्थिति कोई बुरी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहते है कि इस कुव्यवस्था का कारण बढ़ती हुई आबादी और काम का नहीं मिलना है, जब तक हम आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे, लोगों के लिये काम का प्रबन्ध नहीं किया जायेगा तब तक कुव्यवस्था बढ़ेगी। मैं मध्य बिहार में आतंकवाद का

जो इलाका है, नक्सलाईट का जो इलाका है, उसके बारे में कहना चाहता हूँ। मध्य बिहार में, यह बात सह है कि कानून का राज लगभग खत्म हो गया है, इसका कारण क्या है? जैसे नागालैण्ड में, आसाम में, कश्मीर में, आंध्रप्रदेश में उग्रवादी गतिविधियां तेज हैं, वह केन्द्र सरकार की उपेक्षा के चलते है, इसमें केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये, बिहार के उग्रवाद गतिविधियां को रोकने के लिये मदद करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देना हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। प्रेस वालों को भी कहूंगा कि वे सेंसर नहीं करेंगे, हम लोगों के बारे में भी लिखेंगे।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, ने आसन ग्रहण किया।)

(व्यवधान)

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हो गये।)

(व्यवधान)

श्री जगदानन्द सिंह - उनको दो मिनट बोलने का समय दिया जाय।

अध्यक्ष - अब किसी को नहीं। आपके लिये स्पेशल टाईम कल देंगे। आप बैठिये, अब कोई नहीं बोलेंगे, माननीय मंत्री।

श्री जगदानन्द सिंह - अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इस सरकार में विधि-व्यवस्था की क्या स्थिति है इसको संक्षेप में व्याख्या किया जाय तो इस लालू जी की सरकार में धू-धू कर जलता हुआ बिहार, कहीं नरसंहार तो कहीं अत्याचार, कहीं बलात्कार, थाना में बलात्कार-यह है श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार। आखिर सरकार कब तक चलेगी? सरकार में मंत्री की हत्या होती है.

जिनकी सरकार में विधायक की हत्या होती है और वह सरकार पैसा

मांगकर दुरूपयोग करना चाहती है इसलिए हम लोगों ने कटौती प्रस्ताव दिया है। हमारा क्षेत्र पालीगंज है और वहाँ 4-4 नरसंहार हुए हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी गए थे नगमा नरसंहार के समय और साथ में माननीय सदस्य डा० जगदीश शर्मा भी गए थे, उस समय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार को राहत दी जायेगी लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आजतक उनको राहत नहीं दी गयी। यहां तक कि जो लाश होते हैं।, उनके कफन हटाकर उनका चेहरा देखा जाता है, चमड़ी देखकर पूछा जाता है कि तुम्हारा क्या जात है तब मुआवजा उनको दिया जाता है।

अध्यक्ष - यह नहीं, सरकार सब के लिए है, सरकार सारी पब्लिक के लिए है, 9 करोड़ जनता के लिए है।

श्री जनार्दन शर्मा - माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि नगमा नरसंहार हुआ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकत्ता श्री रजनधारी सिंह की हत्या हुई। लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। आखिर क्यों नहीं दिथा गया ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य बिहार में 450 करोड़ परती भूमि में लाल झंडा गाड़ दिया गया है। सरकार के पास रजिस्टर टू होता है। सरकार के पदाधिकारी होते हैं, राजस्व पदाधिकारी होते हैं क्यों नहीं जमीन पर जाते हैं, वहाँ के मामले का समाधान करते हैं लेकिन सरकार की ऐसी नीति है कि आज किसान और मजदूर में लड़ाई बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि माननीय जगदीश शर्मा जी का घर किनके द्वारा ढाया गया। पशुपालन के मामले में जब ये जेल गए तो उनके घर को ढाया गया और एक दूबे जी पदाधिकारी थे उनके घर को भी ढाया गया। वह एम०सी०सी० के लोगों द्वारा ढाया गया। एम०सी०सी० द्वारा कहा जाता है कि अगर लालू प्रसाद जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी आन्दोलन करेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जायगा।